नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 240
दि. 03.06.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

सीबीएसई में बड़ा प्रशासनिक भूचाल: परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों के बीच चेयरमैन और सचिव हटाए गए

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी स्कूली शिक्षा संस्था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) में एक बड़े प्रशासनिक बदलाव ने शिक्षा जगत में हलचल पैदा कर दी है। केंद्र सरकार ने बोर्ड के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटा दिया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब बोर्ड की परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली, विशेष रूप से ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) व्यवस्था और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। लाखों विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षाविदों के बीच लंबे समय से परीक्षा परिणामों की पारदर्शिता और तकनीकी खामियों को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही थी। अब सरकार की इस कार्रवाई को परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, ऑन-स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और टेंडर प्रक्रिया को लेकर मिली शिकायतों ने सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा था। आरोप लगाए गए थे कि मूल्यांकन प्रणाली से जुड़ी तकनीकी सेवाओं की खरीद में पारदर्शिता के मानकों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। इन शिकायतों के सामने आने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच का निर्णय लिया। इसी क्रम में बोर्ड के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों को हटाने का फैसला लिया गया, ताकि जांच निष्पक्ष और बिना किसी प्रभाव के पूरी की जा सके।

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, सीबीएसई ने पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है। यह समिति ऑन-स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद प्रक्रिया, तकनीकी कंपनियों के चयन, अनुबंधों की शर्तों और पूरी मूल्यांकन प्रणाली की कार्यप्रणाली की जांच करेगी। समिति को

यह भी देखना होगा कि क्या किसी स्तर पर नियमों की अनदेखी हुई और यदि हुई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि देश की परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने की कोशिश भी है। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के उद्देश्य से ऑन-स्क्रीन मार्किंग तकनीक अपनाई गई थी। इसका उद्देश्य उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में मानवीय त्रुटियों को कम करना और परिणामों को समय पर जारी करना था। हालांकि हाल के महीनों में छात्रों और शिक्षकों की ओर से कई शिकायतें सामने आईं, जिनमें उत्तरों का गलत मूल्यांकन, अंक जोड़ने में त्रुटियां और तकनीकी खामियों के कारण परिणाम प्रभावित होने जैसी बातें शामिल थीं।

स्थिति तब और गंभीर हो गई जब नए री-इवैल्यूएशन पोर्टल के संचालन के दौरान अनेक तकनीकी समस्याएं सामने आने लगीं। कई छात्रों ने शिकायत की कि उन्हें अपनी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं में आवश्यक पृष्ठ दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ मामलों में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाएं अपलोड नहीं हुईं, जबकि कई विद्यार्थियों ने मानचित्र, ग्राफ और आरेखों के मूल्यांकन में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई। इन शिकायतों ने छात्रों और अभिभावकों के बीच असंतोष बढ़ा दिया।

सरकार का मानना है कि परीक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार की लापरवाही सीधे छात्रों के भविष्य को प्रभावित करती है। यही कारण है कि इस मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई की गई है। शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बीच सीबीएसई ने छात्रों को राहत देने के लिए री-इवैल्यूएशन और उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल उन छात्रों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने अपनी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कर ली हैं। छात्र 2 जून से 6 जून 2026 तक निर्धारित पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नई व्यवस्था के तहत छात्रों को सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर आधार आधारित लॉगिन के माध्यम से प्रवेश करना होगा। आवेदन से लेकर शुल्क भुगतान तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। बोर्ड का दावा है कि डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से शिकायतों के निपटारे में तेजी आएगी और छात्रों को अनावश्यक कार्यालयी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा।

छात्र कई प्रकार की समस्याओं के लिए आवेदन कर सकेंगे। इनमें उत्तर पुस्तिका के पन्नों का गायब होना, अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन में शामिल न होना, मानचित्र या ग्राफ का मूल्यांकन से छूट जाना, स्कैन की गई प्रतियों का धुंधला होना तथा गलत प्रश्नपत्र या गलत उत्तर पुस्तिका के आधार पर मूल्यांकन जैसी त्रुटियां शामिल हैं। बोर्ड ने कहा है कि प्रत्येक शिकायत का तकनीकी और शैक्षणिक स्तर पर अलग-अलग परीक्षण किया जाएगा।

शुल्क संरचना भी निर्धारित कर दी गई है। यदि किसी छात्र को उत्तर पुस्तिका के पन्ने गायब होने या अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका संलग्न न होने जैसी समस्या की शिकायत करनी है तो उसे प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं किसी विशेष उत्तर या प्रश्न के पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। भुगतान केवल डिजिटल माध्यमों से ही किया जा सकेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरा घटनाक्रम देश की परीक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो इससे भविष्य में परीक्षा प्रबंधन और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं छात्रों और अभिभावकों की उम्मीद है कि सरकार की इस सख्त कार्रवाई के बाद मूल्यांकन प्रणाली में सुधार होगा और परिणामों को लेकर पैदा होने वाले विवादों में कमी आएगी।

महंगी पड़ने लगी रसोई गैस: छोटे एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी पर अब देने होंगे अतिरिक्त 25

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में बढ़ते तनाव और कच्चे ईंधन की आपूर्ति को लेकर पैदा हुई अनिश्चितताओं का असर अब भारत के एलपीजी उपभोक्ताओं पर भी दिखाई देने लगा है। हाल के दिनों में एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, जो विशेष रूप से छोटे गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगी। इंडियन ऑयल ने स्पष्ट किया है कि 5 किलोग्राम क्षमता वाले 'छोटू' एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी के लिए ग्राहकों को प्रति रिफिल 25 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ऐसे समय में जब महंगाई पहले से ही आम लोगों के घरेलू बजट पर दबाव बना रही है, यह अतिरिक्त शुल्क उपभोक्ताओं की जेब पर और बोझ डाल सकता है।

वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बनी अस्थिरता के बीच भारत सरकार ने भी पेट्रोलियम कंपनियों को एलपीजी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। बढ़ती मांग और आपूर्ति संबंधी चुनौतियों के कारण एलपीजी की लागत पर दबाव बना हुआ है, जिसका असर समय-समय पर कीमतों में वृद्धि के रूप में दिखाई दे रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों और 5 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडरों की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। 5 किलोग्राम का छोटू सिलेंडर विशेष रूप से उन परिवारों, कामगारों, छात्रों, छोटे दुकानदारों और अस्थायी निवास वाले लोगों के बीच लोकप्रिय है, जिन्हें नियमित घरेलू गैस कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। यह सिलेंडर अपनी आसान उपलब्धता और सरल प्रक्रिया के कारण देशभर में तेजी से लोकप्रिय हुआ है। हालांकि बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि इसकी होम डिलीवरी पर अलग से शुल्क देना पड़ता है। इंडियन ऑयल की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ग्राहक यदि पॉइंट ऑफ सेल्स या अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से छोटू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी मंगवाते हैं तो उन्हें प्रति रिफिल 25 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। कंपनी का कहना है कि यह शुल्क डिलीवरी सेवा और परिवहन लागत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। हालांकि ग्राहक स्वयं जाकर सिलेंडर प्राप्त करते हैं तो उन्हें यह अतिरिक्त राशि नहीं चुकानी पड़ती। छोटू सिलेंडर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी आसान उपलब्धता है। सामान्य घरेलू गैस कनेक्शन लेने के लिए जहां कई दस्तावेजों और पते के प्रमाण की आवश्यकता होती है, वहीं 5 किलोग्राम वाले इस सिलेंडर के लिए केवल पहचान पत्र के आधार पर कनेक्शन लिया जा सकता है। यही कारण है कि प्रवासी मजदूरों, किराए के मकानों में रहने वाले लोगों, छात्रावासों और छोटे व्यवसायों में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। इंडियन ऑयल ने देशभर में इसके वितरण नेटवर्क का विस्तार किया है। ग्राहक इसे किसी भी अधिकृत इंडेन गैस वितरक, इंडियन ऑयल के रिटेल आउटलेट, चुनिंदा किराना दुकानों, सुपरमार्केट तथा अधिकृत पॉइंट ऑफ सेल्स से खरीद सकते हैं। इसकी रीफिलिंग की सुविधा भी देशभर में उपलब्ध है, जिससे उपभोक्ताओं को किसी एक स्थान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।

कंपनी की एक और महत्वपूर्ण सुविधा उपभोक्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यदि कोई ग्राहक छोटू सिलेंडर खरीदने के बाद भविष्य में उसका उपयोग बंद करना चाहता है, तो वह सिलेंडर वापस कर सकता है। इसके बदले कंपनी प्रति सिलेंडर 500 रुपये की निर्धारित राशि वापस करती है। खास बात यह है कि यह राशि सिलेंडर कितने समय तक उपयोग में रहा, इससे प्रभावित नहीं होती। इस सुविधा के कारण उपभोक्ताओं का निवेश सुरक्षित बना रहता है। उधर गैस सिलेंडरों की कीमतों में हालिया वृद्धि ने उपभोक्ताओं की चिंता और बढ़ा दी है। एक जून से 5 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडर की कीमत में 11 रुपये की वृद्धि की गई है। इसके बाद इसकी कीमत बढ़कर 821.50 रुपये हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 810.50 रुपये थी। हालांकि राशि देखने में छोटी लग सकती है, लेकिन बार-बार होने वाली बढ़ोतरी का सीधा असर निम्न और मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है।

केवल छोटू सिलेंडर ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक उपयोग में आने वाले 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में इसकी कीमत 42 रुपये बढ़कर 3,113.50 रुपये हो गई है। इससे पहले यह सिलेंडर 3,071.50 रुपये में उपलब्ध था। होटल, रेस्तरां, ढाबा, कैटरिंग व्यवसाय और छोटे खाद्य प्रतिष्ठान इस बढ़ोतरी से सीधे प्रभावित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि कॉमर्शियल गैस की कीमत बढ़ने से खाद्य पदार्थों की लागत पर भी प्रभाव पड़ सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले मई महीने में भी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी वृद्धि की गई थी। लगातार बढ़ती लागत ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों की परिचालन लागत बढ़ा दी है।

भारत-दक्षिण अफ्रीका संबंधों को नई गति: व्यापार, निवेश और वैश्विक सहयोग के नए अध्याय की ओर बढ़े दोनों देश

नई दिल्ली। बदलते वैश्विक परिदृश्य और उभरती आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अपने रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। दक्षिण अफ्रीका के उप-राष्ट्रपति शिपोकोसा पॉलस माशातिले की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और बहुपक्षीय सहयोग को लेकर व्यापक चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और उप-राष्ट्रपति माशातिले के बीच हुई उच्चस्तरीय वार्ता ने स्पष्ट संकेत दिया कि दोनों देश केवल पारंपरिक मित्रता तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि आर्थिक और वैश्विक साझेदारी को भी नई मजबूती देना चाहते हैं।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के संबंध ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आधार पर दशकों से मजबूत रहे हैं। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से जुड़े संघर्ष और रंगभेद विरोधी आंदोलन में भारत के समर्थन ने दोनों देशों को विशेष रूप से करीब लाया। अब यह संबंध नए दौर में आर्थिक सहयोग और वैश्विक नेतृत्व की साझेदारी के रूप में विकसित होते दिखाई दे रहे हैं। नई दिल्ली में हुई वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति

जताई कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में विकासशील देशों की आवाज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका को मिलकर काम करना होगा।

उप-राष्ट्रपति माशातिले ने बातचीत के बाद कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों का दायरा केवल कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में भी इसे व्यापक रूप से विस्तार दिया जाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से आर्थिक सहयोग को भविष्य की साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण आधार बताया। उनका कहना था कि भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाएं हैं और यदि दोनों देश अपने संसाधनों, तकनीकी क्षमता और बाजारों का बेहतर उपयोग करें तो यह सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

वार्ता के दौरान भारत-दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (SACU) मुक्त व्यापार समझौते का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। दक्षिण अफ्रीका ने इस समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्त की। माना जा रहा है कि यदि यह समझौता लागू होता है तो भारत और दक्षिणी अफ्रीका के देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को नया प्रोत्साहन मिलेगा। इससे शुल्क संबंधी बाधाएं कम होंगी और निवेश के अवसरों में वृद्धि होगी। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि मुक्त व्यापार समझौता दोनों क्षेत्रों के उद्योगों, कृषि और सेवा क्षेत्र के लिए नए बाजारों के द्वार खोल सकता है। उप-राष्ट्रपति माशातिले ने अपनी यात्रा के दौरान भारतीय उद्योग जगत और विभिन्न राजनीतिक हस्तियों से भी मुलाकात की। इनमें राज्यसभा सदस्य डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी सहित कई प्रमुख व्यक्तित्व शामिल रहे। इन बैठकों का उद्देश्य दोनों देशों के निजी क्षेत्र के बीच निवेश और व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा देना था। दक्षिण अफ्रीका विशेष रूप से भारत की तकनीकी विशेषज्ञता, डिजिटल अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकास मॉडल में रुचि दिखा रहा है।

इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लोगों से लोगों के संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में हुई चर्चा भी रही। दक्षिण अफ्रीका के उप-राष्ट्रपति ने भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन से मुलाकात कर दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं ने माना कि राजनीतिक और आर्थिक संबंधों की मजबूती के साथ-साथ शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर भी सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। बैठक के दौरान वैश्विक दक्षिण यानी 'ग्लोबल साउथ' के मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में रहे। भारत और दक्षिण अफ्रीका लंबे समय से विकासशील देशों के हितों की वकालत करते रहे हैं। दोनों देशों का मानना है कि वैश्विक संस्थाओं और निर्णय प्रक्रिया में विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में ब्रिक्स, जी-20, आईबीएसए और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) जैसे मंचों पर सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।

कर्नाटक में नई सत्ता का अध्याय आज से शुरू डीके शिवकुमार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

बेंगलुरु। कर्नाटक की राजनीति में बुधवार का दिन ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। लंबे राजनीतिक अनुभव, संगठनात्मक कौशल और कांग्रेस के मजबूत जनाधार वाले नेता डीके शिवकुमार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य की कमान संभालेंगे। राजधानी बेंगलुरु के लोक भवन परिसर में आयोजित होने वाले भव्य समारोह में शाम 4 बजकर 5 मिनट पर राज्यपाल उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। उनके साथ मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्य भी शपथ ग्रहण करेंगे, जबकि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर आगे और चरणों में निर्णय लिए जाने की संभावना है।

शिवकुमार के शपथ ग्रहण के साथ ही कर्नाटक में कांग्रेस शासन का नया अध्याय शुरू होगा। हालिया विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने कई दौर की बैठकों और विचार-विमर्श के बाद उन्हें कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना था। 30 मई को औपचारिक रूप से विधायक दल की

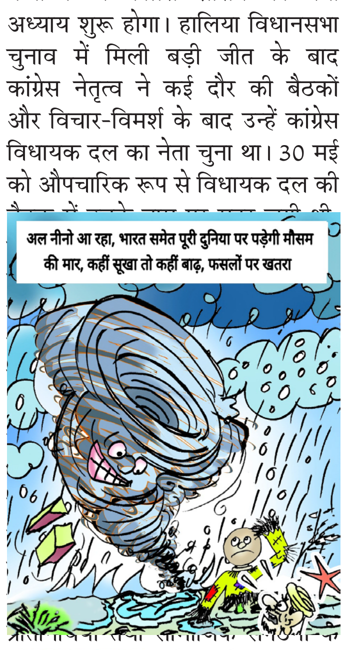

प्रमुखों के शामिल होने की संभावना है। हालांकि शपथ ग्रहण से पहले सबसे अधिक चर्चा नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर रही। मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने से पहले डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने नई दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ लंबी बैठकें कीं। दोनों नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा संगठन के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रिमंडल के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की। इन बैठकों में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, जातीय संतुलन, अनुभव और संगठनात्मक योगदान जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया।

कर्नाटक में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 34 मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने का संवैधानिक प्रावधान है। ऐसे में सीमित पदों के बीच विभिन्न क्षेत्रों और समूहों को प्रतिनिधित्व देना शिवकुमार के लिए आसान नहीं होगा। कांग्रेस की चुनावी जीत में कई वरिष्ठ नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बड़ी संख्या में विधायक मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी कारण मंत्रिमंडल गठन को लेकर राजनीतिक हलकों में उत्सुकता चरम पर है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवकुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने की होगी। मंत्री पद से वंचित रह जाने वाले नेताओं की नाराजगी यदि समय रहते नहीं संभाली गई तो वह सरकार और संगठन दोनों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। पिछले कुछ दिनों में अनेक विधायक और पूर्व मंत्री दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस आलाकमान के समक्ष अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुके हैं। कई नेताओं ने सीधे शिवकुमार और सिद्धारमैया से मुलाकात कर अपनी राजनीतिक अपेक्षाएं भी रखी हैं।

सूत्रों के अनुसार नए मंत्रिमंडल में अनुभवी और युवा नेताओं का मिश्रण देखने को मिल सकता है। कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि सरकार में अनुभव का लाभ भी मिले और नई पीढ़ी को भी पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए। इसी कारण कई नए चेहरों को मंत्री पद मिल सकता है, जबकि कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है।

मंत्रिमंडल गठन में जातीय और सामाजिक समीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत, वोक्कालिगा, दलित, ओबीसी, मुस्लिम तथा अन्य समुदायों का संतुलित प्रतिनिधित्व हमेशा से अहम माना जाता रहा है। चूंकि डीके शिवकुमार स्वयं वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं, इसलिए मंत्रिमंडल में अन्य प्रभावशाली सामाजिक समूहों को भी पर्याप्त स्थान दिए जाने की संभावना है। साथ ही सिद्धारमैया समर्थक नेताओं को भी उचित प्रतिनिधित्व देकर पार्टी के भीतर एकजुटता बनाए रखने की कोशिश की जाएगी।

राजनीतिक सूत्रों का यह भी कहना है कि नए मंत्रिमंडल में एक से अधिक उपमुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इससे विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों को राजनीतिक संदेश देने में मदद मिलेगी। कांग्रेस नेतृत्व आगामी लोकसभा चुनावों और राज्य की दीर्घकालिक राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल की संरचना तय कर रहा है।

डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कई जनकल्याणकारी वादे किए थे और अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि नई सरकार उन वादों को किस गति से लागू करती है। बेरोजगारी, कृषि, निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दे नई सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहने की संभावना है।

आज का शपथ ग्रहण समारोह केवल सत्ता परिवर्तन का औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि कर्नाटक की राजनीति में नए नेतृत्व और नई दिशा की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि डीके शिवकुमार अपनी पहली कैबिनेट कैसी बनाते हैं और राज्य की राजनीति में स्थिरता, विकास तथा संगठनात्मक संतुलन को किस तरह साधते हैं।

संपादकीय

आईपीएल में अनुभव और युवा जोश का संगम

भले ही फटाफट क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाला आईपीएल बाजार और नई पीढ़ी के जुनून का संगम हो, लेकिन लोकप्रियता के नये आयाम तय करता यह खेल अब दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की पहली पसंद बन गया है। इस बार इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे चमकीले सितारे बनकर उभरे टी-20 सनसनी वैभव सूर्यवंशी। महज पंद्रह साल की उम्र में उनकी कामयाबी हैरत में डालने वाली है। वहीं अनुभवी क्रिकेटर विराट कोहली ने अपने खास अंदाज में सबका ध्यान आकर्षित किया। इस 37 वर्षीय दिग्गज क्रिकेटर ने फाइनल में तूफानी अर्धशतक लगाकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को लगातार दूसरी बार ट्राफी दिलाई। दो महीने तक चले इस टूर्नामेंट में कोहली की फॉर्म और फिटनेस शानदार रही है। यही वजह है कि वर्ष 2027 एकदिवसीय क्रिकेट के विश्व कप में उनकी भागीदारी अब लगभग तय लग रही है। खुद कोहली ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें अपनी मनःस्थिति में बदलाव लाने और युवा खिलाड़ियों से थोड़ा सीखने की जरूरत थी, ताकि वे टी-20 क्रिकेट में अपने खेल को नये सिरे से निखार सकें। यह सुखद ही है कि इस दिग्गज क्रिकेटर की यह ईमानदार स्वीकारोक्ति भारतीय क्रिकेट को आकार दे रही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की खूबसूरत बानगी को ही दर्शाती है। निस्संदेह, हाल ही में संपन्न हुए इंडियन प्रीमियर लीग सीजन ने साफ दिखाया कि दो पीढ़ियों के क्रिकेटर कैसे एक-दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। वास्तव में, विराट कोहली आज भी एक प्रभावशाली खिलाड़ी की छवि को बनाये हुए हैं। वहीं वैभव सूर्यवंशी जैसे उदीयमान खिलाड़ी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस फटाफट क्रिकेट में खेल का निरंतर विकास होता रहेगा। यह सुखद ही है कि राजस्थान रॉयल्स के इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी सूर्यवंशी ने अधिकांश पुरस्कार अपने नाम किए हैं। मसलन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, सुपर स्ट्राइक ऑफ द सीजन, ऑरेंज कैप विजेता और सुपर सिक्स ऑफ द सीजन जैसे खिताब हासिल किए।

इसमें दो राय नहीं कि वैभव सूर्यवंशी के क्रिकेट के वैभव ने आज पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। क्रिकेट की दुनिया के तमाम दिग्गज क्रिकेटर इस उदीयमान खिलाड़ी के क्रिकेट के कारनामों से हतप्रभ हैं। वे वैभव को आशीष व अनुभव दे रहे हैं। यहां तक कि सचिन तेंदुलकर ने उसे अपना स्वाभाविक क्रिकेट खेलने की सलाह तक दी है। इतना ही नहीं, भारत के चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान में भी वैभव को पूरा लाड मिल रहा है। पूरे पाकिस्तान में उसकी खेल तकनीक की खूब चर्चा होती है। निस्संदेह, उनकी निडर बल्लेबाजी और उल्लेखनीय रूप से निरंतर बेहतर खेलना, क्रिकेट के छोटे प्रारूप के प्रति नई पीढ़ी के साहसिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। हालांकि, उनकी प्रतिभा को लगातार अभ्यास से हासिल व कुछ लोगों द्वारा नैसर्गिक प्रतिभा कहा जा रहा है, लेकिन चर्चा उनकी इतनी कम उम्र में हासिल परिपक्वता को लेकर भी है। सही मायने में दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की सूर्यवंशी की क्षमता ठीक उसी गुण को दर्शाती है,जिसने वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोहली की सफलता का मार्ग प्रशस्त किया है। निस्संदेह, मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग के संस्करण में, जिस तरह क्रिकेट प्रतिभाओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी नजर आती है, उसे टी-20 विश्व चैंपियन भारत के लिये शुभ संकेत ही कहा जा सकता है। यह सुखद ही है कि वर्ष 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों तथा वर्ष 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में टी-20 क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। ऐसे में भरोसा बढ़ता है कि क्रिकेट को दीवानगी के साथ जीने वाले इस देश को आने वाले वर्षों में क्रिकेट की कई बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। विश्वास किया जाना चाहिए कि दुनिया का सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई महिला क्रिकेट को भी पुरुष क्रिकेट के समान निखरने हेतु संबल देगा। हालांकि, भारत में महिला टी-20 क्रिकेट की घरेलू श्रृंखलाएं आरंभ हो चुकी हैं, लेकिन अभी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना बाकी है। ताकि भारत क्रिकेट के सभी प्रारूपों में अपनी बादशाहत कायम रख सके।

चीन की दूरदृष्टि से सबक लेने की जरूरत

> “दुनिया में तेज बदलावों व हालिया युद्धों से उपजे ऊर्जा संकट और चीन-पाक के गठजोड़ जैसी चुनौतियों से पार पाने को देश को सूझवान नेतृत्व और कूटनीति की जरूरत है। दूरदर्शी योजनाओं से चीन ने ऊर्जा, रेयर अर्थ, इवी और बैटरी क्षेत्रों में जबरदस्त क्षमता हासिल की। वहीं भारत ऊर्जा के लिए आयातों पर निर्भर है।

ब्लूमबर्ग न्यूज़ की 28 जनवरी, 2026 की खबर के अनुसार, चीन ने पिछले साल सभी तकनीकी क्षेत्रों में 543 गीगावाट जितनी नई बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भारत में 2024 के आखिर तक के पैदा हुए कुल बिजली उत्पादन से 12 प्रतिशत ज़्यादा है। चीन की इस बढ़ोतरी में 80 फीसदी से ज़्यादा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का था, जिसमें सोलर व पवन ऊर्जा शामिल हैं। वहीं यूएस एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक तेल भंडार है (लगभग 1.4 अरब बैरल)। दिलचस्प कि उसने 2025 में अपने तेल भंडारण में काफ़ी वृद्धि की, और रूस, ईरान और वेनेज़ुएला से रियायती दरों पर करोड़ों बैरल तेल खरीदा। जबकि भारत के पास सिर्फ़ 21 मिलियन बैरल का तेल भंडार था।

पिछले कुछ दशकों में, चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उत्पादन, लिथियम-आयन बैट्री उत्पादन और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में अपनी ज़बरदस्त रणनीतिक बढ़त बनाई है। चीनी लोग इस समूची मूल्य संवर्धन श्रृंखला में अब दुनियाभर में अग्रणी हैं। ऐसा कर उन्होंने न केवल जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम की और प्रदूषण घटाया बल्कि जीवाश्म ईंधन से दूर हटती दुनिया के दौर में अपनी बहुत मज़बूत स्थिति भी बना ली। रेयर अर्थ मिनरल, ईवी निर्माण, बैट्री उत्पादन व स्वच्छ ऊर्जा की यह तिकड़ी, किसी अर्थव्यवस्था की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता खत्म करने का ‘सबसे अहम माध्यम’ है।

यह सब सावधानी से की गई योजनाबंदी से हासिल हो पाया, जिसे पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष स्थान दिया गया (अभी वहां 15वीं योजना चल रही है)। ये योजनाएं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति और राज्य परिषद (चीनी कैबिनेट) मिलकर बनाती हैं। यह रणनीतिक बढ़त ही तय करेगी कि देश आगामी ऊर्जा संकट से कैसे निबटेगा। यह ऊंची और नीची महंगाई दर वाले देशों के बीच का फ़र्क बनाता है, और यह तय करने में एक अहम भूमिका निभाएगा कि एआई के युग में डेटा सेंटर कहां स्थापित होंगे, क्योंकि

स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, भंडारण, रेयर अर्थ मिनरल और डेटा सेंटरों के बीच एक रणनीतिक सांझ है। बीते साल चीन ने अपने रणनीतिक अस्त्र का इस्तेमाल किया व रेयर अर्थ के निर्यात पर रोक लगाकर भारत का ईवी उत्पादन करीब ठप कर दिया था (इस क्षेत्र में उसका लगभग एकाधिकार है)।

देश -अपनी सरकारों के ज़रिए- भविष्य के लिए योजना बनाते हैं। ऐसी योजना में विगत के और मौजूदा अनुभवों का गहराई से विश्लेषण करना शामिल होता है, साथ ही भविष्य के संभावित बदलावों के बारे में भी अनुमान भी लगाए जाते हैं। उपरोक्त अवयवों के आधार पर, सरकार भविष्य से निबटने को नीतियां बनाती है। जब हम खुद को और अपनी मौजूदा स्थिति को, खासकर ऊर्जा की स्थिति और उसके नतीजों के मामले में, देखते हैं, तो लगता है कि हमने पिछले कुछ दशक में जरूरी तैयारी नहीं की।

चूंकि भारत का अपना तेल का उत्पादन बहुत कम है, इसलिए यह यकीनी बनाना केंद्र की ज़िम्मेदारी है कि आपात स्थिति में संसाधन उपलब्ध रहें, पर्याप्त भंडार बनाए, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह कि बड़े पैमाने पर हरित ऊर्जा अपनाएं, ताकि हम आयातित कच्चे तेल पर बिल्कुल निर्भर न रहें। जहां यह बात तसल्ली देने वाली है कि हमारी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का आधा हिस्सा अब नवीकरणीय स्रोतों से आता है, लेकिन कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन का हिस्सा अभी भी सबसे अधिक (लगभग 42 प्रतिशत) है। अहम बात यह है कि यह अभी भी कुल बिजली खपत का 70 प्रतिशत हिस्सा मुहैया करवाता है, जबकि भारत ने अभी तक बिजली के भंडारण की पर्याप्त क्षमता विकसित नहीं की। जबकि चीन ने इस मामले में बहुत काम किया है। यह दशक लगातार उथल-पुथल भरा रहा। पहले कोविड महामारी, फिर पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया युद्ध जो जारी हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उद्भव। भारत औद्योगिक क्रांति करने से चूक गया था, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। देश ‘80 और ‘90 के दशक के कंप्यूटर-प्रधान युग के शुरुआती दौर में भी चूक कर गया; ‘90 के दशक के आर्थिक सुधार तब जाकर लागू किए, जब देश करीब दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। शुक्र है, निजी क्षेत्र ने आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी संभाली, साथ ही तकनीकी विशेषज्ञों की बड़ी फौज ने भी स्थिति से उबारने में मदद की। हालांकि भारत अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी नहीं बन पाया, आईटी क्षेत्र में उसकी जगह अधिकांशतः सेवा आधारित क्षेत्र में ही है।

हालांकि देर से हुई शुरुआत के मद्देनज़र, काबिल-ए-तारीफ है कि हम इतनी प्रगति कर पाए। एआई से आ रहे बड़े बदलावों की बात करें तो, हमने एक बार फिर मौका गंवा डाला है और अब हम उसे तेज़ी से दूर जाते हुए देख सकते हैं। सेमीकंडक्टर उत्पादन में हमारी कोई जगह नहीं, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आपूर्ति के लिए एशियाई दिग्गजों- ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन पर निर्भर बना हुआ है। जिन डेटा सेंटर्स की स्थापना की योजना बनाई जा रही, वे भी दूसरों पर निर्भर रहेंगे। अमेरिका और चीन ने एआई और उससे जुड़े बुनियादी ढांचा निर्माण में बहुत बड़ी छलांग लगाई। इस आधारभूत ढांचे में बेहतरीन चिप बनाना, सस्ती बिजली और सरकार का योगदान बतौर सुधारक और मददगार होना शामिल है। एनवीडिया सरीखी कंपनियां अब खरबों डॉलर मूल्य की बन चुकी हैं और एआई तकनीक का प्रवाह नियंत्रित करती हैं। किसे ये चिप्स मिल सकती हैं और किसे नहीं, अमेरिका ही तय करता है। एएसएमएल जैसी डच कंपनियां -जो बेहतरीन क्वालिटी के माइक्रोचिप्स उत्पादन के लिए मशीनें बनाती हैं और इस क्षेत्र में उनका करीब एकाधिकार है- सिर्फ़ उनको ही बेच सकती हैं, जिसकी इज़ाजत अमेरिका देता है।

इन सब के बीच हम कहां खड़े हैं? क्या हम एक बार फिर से केवल सेवा और रखरखाव प्रदाता बनने की उम्मीद पाले हैं? जिस स्तर का ऑटोमेशन व रोबोटिक्स सामने आ रहा है, उसे देखकर लगता है, हमारी यह भूमिका भी बहुत छोटी होकर रह जाएगी।

एआई के इस दौर में, अपनी बादशाहत कायम करने की होड़ में जब अलग-अलग देशों के रणनीतिक हित आपस में टकरा रहे हैं, तो ऐसे में एक समझदार और दूरदर्शी नेतृत्व की ज़रूरत है। एआई आधारभूत तंत्र विकास और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक साझेदारियां बनाने में विदेश नीति और कूटनीति की अहम भूमिका होगी। आज की तारीख में, यहां तक कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ग्रिड स्टोरेज के हेतु बैट्री बनाने की हमारी क्षमता चीन से आयातित ‘दुर्लभ खनिजों’ पर निर्भर है (इस क्षेत्र में भी चीन का लगभग एकाधिकार)। रणनीतिक गठबंधनों की ज़रूरत हमें गैस की कमी, और पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध के कारण ‘स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़’ के बंद हो जाने से पैदा हुई उर्वरकों और कच्चे तेल की संभावित कमी व आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों के रूप में साफ़ दिखती है। हमें मजबूरन हाथ-पैर मारने पड़ रहे, दूसरों से मदद मांगनी पड़ी। रूस संग हमारा भी समझौता था, चीन की तरह, लेकिन रूस पर प्रतिबंधों का सर्वाधिक नुकसान हमें उठाना पड़ा।

इसी तरह, अब हमें ईरान से भी तेल नहीं मिल पा रहा है। हमारी भंडारण क्षमता भी सीमित है, और हमने हाल ही में यूएई के साथ मिलकर बड़े-बड़े तेल भंडार बनाने का समझौता किया है... लेकिन इसको फलीभूत होने में अभी काफ़ी समय लगेगा। अमेरिका-ईरान युद्धबंदी वार्ता नाकाम होना हमारे लिए और भी ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा और इससे अफ़रा-तफ़री मच सकती है - ऐसी स्थिति से हम अब तक किसी तरह बचे हुए थे। इसके साथ ही, अमेरिका पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल की पीठ ठोक रहा है, और ईरान के मामले में उस पर एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में भरोसा करता है। आर्थिक दुश्वारियों से राहत पाने में अमेरिका ने विश्व बैंक के ज़रिए उसकी मदद की है।

भारत की मुश्किलों को और बढ़ाने वाली बात है चीन और पाकिस्तान के बीच के करीबी रिश्ते। चीन की अपनी हालिया यात्रा के दौरान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ का स्वागत राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया, और दोनों के बीच की ‘पहाड़ों से भी ऊंची’ दोस्ती का वचन एक बार फिर दोहराया। जारी संयुक्त बयान में, लंबे समय से चले आ रहे ‘जम्मू और कश्मीर विवाद’ को सुलझाने की बात कही गई ।

प्रेरणा

ज्ञान का वास्तविक मूल्यः जब प्रतिभा समाज की सेवा बन जाए

ज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है, लेकिन उसका वास्तविक महत्व केवल उसे प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उसके सदुपयोग में निहित है। इतिहास ऐसे अनेक व्यक्तित्वों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए किया। ऐसे ही महान व्यक्तियों में वैज्ञानिक जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका जीवन इस बात का प्रेरणादायक उदाहरण है कि सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन उन गरीब किसानों की सहायता में समर्पित कर दिया जो आर्थिक कठिनाइयों, कम उत्पादन और बंजर होती जमीन की समस्याओं से जूझ रहे थे। कार्वर का मानना था कि विज्ञान का उद्देश्य केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यही सोच उन्हें अन्य वैज्ञानिकों से अलग बनाती थी। एक बार अमेरिका की एक बड़ी औद्योगिक कंपनी ने कार्वर को अत्यंत आकर्षक वेतन और आधुनिक सुविधाओं के साथ नौकरी का प्रस्ताव दिया। उस समय यह अवसर किसी भी व्यक्ति के लिए एक सपना माना जा सकता था। कंपनी के प्रतिनिधि स्वयं उनसे मिलने पहुंचे और उन्हें समझाया कि यदि वे कंपनी से जुड़ जाएं तो उन्हें अपार धन, प्रतिष्ठा और अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं प्राप्त होंगी। यह प्रस्ताव इतना आकर्षक था कि अधिकांश लोग बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्वीकार कर लेते।

कार्वर ने प्रतिनिधियों की बात पूरी गंभीरता से सुनी। वे जानते थे कि यह प्रस्ताव उनके जीवन को आर्थिक रूप से पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, “यदि मैं यह प्रस्ताव स्वीकार कर लूं, तो क्या मैं उन गरीब किसानों के साथ काम कर पाऊंगा जिनके लिए मैं अभी काम करता हूं?” प्रतिनिधि ने स्पष्ट उत्तर दिया कि कंपनी में शामिल होने के बाद उनका अधिकांश समय कंपनी के अनुसंधान कार्यों में व्यतीत होगा और किसानों के लिए काम करने का अवसर बहुत सीमित रह जाएगा। यह सुनकर कुछ क्षणों के लिए वातावरण में मौन छा गया। कार्वर खिड़की के पास जाकर बाहर खेतों की ओर देखने लगे। उन खेतों में उन्हें केवल मिट्टी नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि उन किसानों का संघर्ष दिखाई दे रहा था जो दिन-रात मेहनत करने के बावजूद गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्हें याद आया कि कैसे वर्षों से वे किसानों को नई खेती तकनीकों, फसल चक्र प्रणाली और उपयोगी फसलों के बारे में जानकारी देकर उनकी स्थिति सुधारने का प्रयास कर रहे थे।

कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधियों से कहा, “आपका प्रस्ताव अत्यंत उदार है, लेकिन मेरा काम अभी यहां पूरा नहीं हुआ है।” यह सुनकर प्रतिनिधि आश्चर्यचकित रह गए। उनके लिए यह समझना कठिन था कि कोई व्यक्ति इतनी बड़ी धनराशि और प्रतिष्ठा को क्यों ठुकरा सकता है। लेकिन कार्वर के लिए जीवन का उद्देश्य केवल धन अर्जित करना नहीं था। वे अपने ज्ञान का उपयोग उन लोगों के लिए करना चाहते थे जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। समय बीतता गया। कार्वर किसानों के साथ काम करते रहे और उन्होंने कृषि के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनकी खोजों और सुझावों से हजारों किसानों का जीवन बेहतर हुआ। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता में निहित होती है। कुछ वर्षों बाद एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि उन्होंने इतना बड़ा अवसर क्यों छोड़ दिया था। कार्वर ने मुस्कराते हुए जो उत्तर दिया, वह आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा, “मैंने जीवन में यह जानने की कोशिश की है कि मेरे पास कितना धन है, उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मैं किस काम के लिए आवश्यक हूं।”

यह कथन जीवन का एक गहरा सत्य प्रकट करता है। आज के समय में अधिकांश लोग सफलता को धन, पद और प्रसिद्धि के आधार पर मापते हैं। समाज में व्यक्ति की पहचान अक्सर उसकी आर्थिक स्थिति से की जाती है। लेकिन यदि केवल धन ही सफलता का मापदंड होता, तो इतिहास उन लोगों को कभी याद नहीं रखता जिन्होंने मानवता की सेवा के लिए अपने स्वार्थों का त्याग किया। वास्तविक सफलता उस संतोष में छिपी होती है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने से प्राप्त होता है। ज्ञान का सदुपयोग तभी संभव है जब उसके साथ संवेदनशीलता, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जुड़ी हो। यदि ज्ञान केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग किया जाए, तो उसका प्रभाव सीमित रह जाता है। लेकिन जब वही ज्ञान समाज की समस्याओं के समाधान में लगाया जाता है, तब वह लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। डॉक्टर अपने ज्ञान से रोगियों को स्वस्थ करते हैं, शिक्षक अपने ज्ञान से नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं और वैज्ञानिक अपने ज्ञान से मानव जीवन को बेहतर बनाते हैं। इन सभी का कार्य तभी सार्थक होता है जब उनका उद्देश्य केवल स्वयं का विकास नहीं, बल्कि समाज का कल्याण भी हो। कार्वर की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में निर्णय केवल आर्थिक लाभ देखकर नहीं लेने चाहिए। कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं जो बाहर से अत्यंत आकर्षक दिखाई देते हैं, लेकिन वे हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य से दूर कर सकते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि उसका ज्ञान और क्षमता किस दिशा में सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में जहां अधिकांश लोग अधिक वेतन, बड़ा पद और भौतिक सुख-सुविधाओं की दौड़ में लगे हैं, वहां जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर का जीवन हमें एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। वे बताते हैं कि व्यक्ति की महानता उसके बैंक खाते की राशि से नहीं, बल्कि उसके द्वारा समाज को दिए गए योगदान से निर्धारित होती है। ज्ञान का सर्वोच्च उपयोग वही है जो मानवता की सेवा में लगे। अंततः, ज्ञान का वास्तविक मूल्य उसके संग्रह में नहीं, बल्कि उसके सदुपयोग में है। जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा और बुद्धि का उपयोग केवल स्वयं के लिए करता है, वह सीमित सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो अपने ज्ञान को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर देता है, वह लोगों के हृदयों में अमर हो जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर का जीवन इसी महान सत्य का जीवंत उदाहरण है कि मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि उसके पास कितना है, बल्कि यह है कि उसने अपने ज्ञान और क्षमता से कितनों का जीवन बेहतर बनाया है।

PM Modi की बड़ी रणनीतिक जीत! China को मिला करारा जवाब

भारत और म्यांमार के बीच संबंधों को नई रणनीतिक धार देने वाली उच्चस्तरीय वार्ता ने दक्षिण पूर्व एशिया की बदलती भू राजनीतिक तस्वीर में बड़ा संदेश दिया है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुनकर साफ संकेत दिया कि वह चीन की बढ़ती पकड़ से संतुलन बनाने के लिए नई दिल्ली के साथ संबंधों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि ह्लाइंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट आश्वासन दिया कि म्यांमार की धरती का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। यह संदेश केवल चीन के लिए ही नहीं बल्कि म्यांमार में सक्रिय उन सशस्त्र गुटों के लिए भी था जो लंबे समय से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति फैलाने की कोशिश करते रहे हैं। इस वार्ता के जरिए भारत ने म्यांमार में चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देते हुए यह दिखा दिया कि क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और सामरिक साझेदारी के मामले में नई दिल्ली अब अधिक आक्रामक और निर्णायक भूमिका निभा रही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वार्ता के बाद बताया कि दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों को लेकर सहयोग पर गंभीर चर्चा हुई। यह क्षेत्र आज वैश्विक राजनीति और आर्थिक प्रतिस्पर्धा का अहम हिस्सा बन चुका है क्योंकि आधुनिक प्रौद्योगिकी, रक्षा उपकरण, ऊर्जा परिवर्तन और अर्धचालक उद्योग में इन खनिजों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत लंबे समय से इन संसाधनों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में प्रयासरत है। ऐसे में म्यांमार के साथ सहयोग भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। म्यांमार दुर्लभ मृदा संसाधनों से समृद्ध देश है और भारत इस क्षेत्र में साझेदारी के माध्यम से अपनी आपूर्ति श्रृंखला को अधिक सुरक्षित और विविध बनाना चाहता है।

दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा, क्षमता निर्माण और सीमा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत म्यांमार का विश्वसनीय पड़ोसी, भरोसेमंद सहयोगी और संकट के समय सबसे पहले सहायता पहुंचाने वाला देश बना रहेगा। यह दृष्टिकोण भारत की ‘पड़ोसी प्रथम’, ‘एक्ट ईस्ट’ और ‘महासागर’ नीति के अनुरूप है।

वार्ता में सुरक्षा सहयोग सबसे महत्वपूर्ण विषयों में शामिल रहा। म्यांमार के राष्ट्रपति ने भारत को आश्वासन दिया कि उनकी भूमि का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। यह आश्वासन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और म्यांमार के बीच लगभग सोलह सौ चालीस किलोमीटर लंबी सीमा है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे संवेदनशील पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ी हुई है। हम आपको बता दें कि हाल के वर्षों में म्यांमार के भीतर अस्थिरता, सशस्त्र समूहों की गतिविधियां, अवैध तस्करी और सीमा पार घुसपैठ भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती रही हैं। विशेष रूप से मणिपुर में जातीय तनाव और हिंसा के बाद सीमा प्रबंधन का महत्व और बढ़ गया है। भारत और म्यांमार के बीच रक्षा सहयोग का केंद्र प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और संस्थागत विकास रहा है। विदेश सचिव ने कहा कि म्यांमार के सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों से जुड़े प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। साथ ही दोनों देशों ने संपर्क परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। विशेष रूप से कलादान बहु माध्यम पारगमन परिवहन परियोजना को रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को म्यांमार के रास्ते दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ा जाएगा। इससे न केवल व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, बल्कि पूर्वोत्तर भारत का रणनीतिक महत्व भी बढ़ेगा। यह परियोजना भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति का प्रमुख आधार मानी जाती है।

देखा जाये तो इस पूरी वार्ता का एक महत्वपूर्ण पहलू चीन के बढ़ते प्रभाव की पृष्ठभूमि भी है। दक्षिण पूर्व एशिया में चीन लगातार आर्थिक और सामरिक विस्तार कर रहा है। म्यांमार में भी चीन की बड़ी निवेश परियोजनाएं और बंदरगाह विकास योजनाएं चल रही हैं। ऐसे में भारत म्यांमार के साथ संबंधों को मजबूत कर क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना चाहता है। भारत के लिए म्यांमार केवल पड़ोसी देश नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला सामरिक द्वार है। इसलिए नई दिल्ली इस संबंध को आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा तीनों स्तरों पर मजबूत करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार में शांति, स्थिरता और समावेशी संवाद के समर्थन की भी बात कही। भारत ने संघीय शासन व्यवस्था और आर्थिक विकास के अपने अनुभव साझा करने की पेशकश की। यह संकेत देता है कि भारत म्यांमार में स्थिर राजनीतिक व्यवस्था और दीर्घकालिक शांति को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक मानता है।

हम आपको यह भी बता दें कि म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से भी महत्वपूर्ण मुलाकात की। इन बैठकों में सीमा सुरक्षा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी गुटों की गतिविधियां, अवैध हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी, समुद्री सुरक्षा तथा क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। भारत ने साफ किया कि म्यांमार की स्थिरता और वहां शांति बहाली भारत की सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई है। अजित डोभाल के साथ हुई बातचीत में सामरिक सहयोग, खुफिया समन्वय और सीमा पार आतंकी नेटवर्क पर निगरानी मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक में व्यापार, संपर्क परियोजनाओं, ऊर्जा सहयोग और पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाली योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।

देखा जाये तो म्यांमार के राष्ट्रपति की यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब पूरा क्षेत्र भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति श्रृंखला संकट और सुरक्षा चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है।

अभियान

बाबा केदार की अद्भुत लीलाः क्यों दुनिया के सबसे अनोखे शिवधामों में गिना जाता है केदारनाथ?

भारत की आध्यात्मिक परंपरा में भगवान शिव का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। वे केवल देवताओं के देव महादेव ही नहीं, बल्कि तप, त्याग, करुणा और अनंत शक्ति के प्रतीक भी हैं। देशभर में भगवान शिव के असंख्य मंदिर मौजूद हैं, लेकिन कुछ तीर्थस्थल ऐसे हैं जिन्हें विशेष रूप से दिव्य और चमत्कारी माना जाता है। उत्तराखंड की हिमालयी वादियों में स्थित केदारनाथ धाम ऐसा ही एक पवित्र स्थल है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचते हैं। समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह धाम न केवल बारह ज्योतिर्लिंगों में शामिल है, बल्कि इसकी पहचान एक ऐसे तीर्थ के रूप में भी है जहां प्रकृति, पुराण और परमात्मा का अद्भुत संगम दिखाई देता है।

केदारनाथ धाम की सबसे बड़ी विशेषता इसका प्राचीन मंदिर और यहां स्थापित अनोखा शिवलिंग है। सामान्य रूप से अधिकांश शिवलिंग गोलाकार या बेलनाकार रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन केदारनाथ में स्थापित शिवलिंग त्रिकोणीय स्वरूप का है। यह आकार न केवल इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है, बल्कि इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा इसे और भी रहस्यमय बना देती है।

हिंदू धर्मग्रंथों में वर्णित मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने राज्य तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए थे। अपने ही कुल, रिश्तेदारों और गुरुओं की मृत्यु का बोझ पांडवों के हृदय पर भारी था। उन्हें लगा कि इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण लेना आवश्यक है।

पांचों पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए निकले। सबसे पहले वे काशी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे। महादेव जानते थे कि युद्ध धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था, फिर भी वे पांडवों की परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए वे काशी छोड़कर हिमालय की ओर चले गए।

पांडव भी उनकी खोज में हिमालय पहुंच गए। यहां भगवान शिव ने स्वयं को छिपाने के लिए एक बैल का रूप धारण कर लिया। वे पशुओं के झुंड में मिल गए ताकि पांडव उन्हें पहचान न सकें। किंतु भीम की दृष्टि अत्यंत तीक्ष्ण थी। उन्होंने एक विशेष बैल को देखा जिसकी चाल और आभा अन्य पशुओं से भिन्न थी। उन्हें संदेह हुआ कि यही भगवान शिव हैं।

भीम ने उस बैल को पकड़ने का प्रयास किया। तभी बैल रूपी महादेव धरती के भीतर समाने लगे। भीम ने पूरी शक्ति लगाकर उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। बैल का अधिकांश भाग भूमि के भीतर विलीन हो गया, जबकि उसका पृष्ठभाग ऊपर रह गया। यही पृष्ठभाग आज केदारनाथ में पूजे जाने वाले त्रिकोणीय शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है।

इस घटना के बाद भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें उनके कर्मों से उत्पन्न दोषों से मुक्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। तभी से यह स्थान भगवान शिव की विशेष कृपा का केंद्र माना जाने लगा।

केदारनाथ की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। मान्यता है कि बैल के शरीर के अन्य अंग भी विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। इन स्थानों को आज पंचकेदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ में पृष्ठभाग, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मदमहेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाएं प्रकट हुईं। पंचकेदार यात्रा आज भी उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है।

केदारनाथ के त्रिकोणीय शिवलिंग को लेकर अनेक आध्यात्मिक व्याख्याएं भी प्रचलित हैं। कुछ विद्वान इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त शक्ति का प्रतीक मानते हैं। वहीं कई साधक इसे सृष्टि, स्थिति और संहार की तीन मूल शक्तियों का प्रतिनिधि बताते हैं। भारतीय दर्शन में त्रिकोण को ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक माना गया है। इसलिए केदारनाथ का शिवलिंग केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश का भी प्रतीक है।

केदारनाथ मंदिर की स्थापत्य कला भी अत्यंत अद्भुत है। विशाल पत्थरों से निर्मित यह मंदिर हिमालय की कठोर परिस्थितियों में भी सदियों से अडिग खड़ा है। यह बात आज भी शोधकर्ताओं और वास्तु विशेषज्ञों को आश्चर्यचकित करती है कि इतनी ऊंचाई और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में प्राचीन काल में इतने विशाल पत्थरों से मंदिर का निर्माण कैसे किया गया होगा। मान्यता है कि वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने आठवीं शताब्दी में कराया था। उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में धार्मिक पुनर्जागरण का कार्य किया और अनेक प्राचीन तीर्थों को पुनः स्थापित किया। केदारनाथ भी उनके महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल माना जाता है। मंदिर के पीछे स्थित बर्फ से ढकी चोटियां इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। जब सुबह की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ती है, तब पूरा वातावरण अलौकिक दिखाई देता है। श्रद्धालु इसे केवल प्राकृतिक दृश्य नहीं, बल्कि दिव्य अनुभव मानते हैं।

केदारनाथ धाम का एक और विशेष पहलू इसकी कठिन यात्रा है। प्राचीन समय में यहां पहुंचना अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। आज आधुनिक सुविधाओं के बावजूद यात्रियों को कई किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा भी मानी जाती है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि बाबा केदार की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति यहां तक नहीं पहुंच सकता।

वर्ष 2013 में आई विनाशकारी आपदा ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था। तेज बारिश और बाढ़ के कारण भारी तबाही हुई। हजारों लोगों की जान चली गई और अनेक भवन नष्ट हो गए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। मंदिर के पीछे आकर रुकी एक विशाल चट्टान ने पानी और मलबे के प्रवाह को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। इस घटना के बाद श्रद्धालुओं की आस्था और भी मजबूत हो गई।

आज वह चट्टान ‘भीम शिला’ के नाम से प्रसिद्ध है। लोग इसे भगवान शिव की दिव्य रक्षा का प्रतीक मानते हैं। हजारों श्रद्धालु मंदिर दर्शन के साथ-साथ भीम शिला के दर्शन भी करते हैं।

धार्मिक मान्यता है कि केदारनाथ में भगवान शिव विशेष रूप से अपने भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं। यहां की पूजा-पद्धति भी अन्य शिव मंदिरों से कुछ अलग है। श्रद्धालु शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं और घी अर्पित कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

स्कंद पुराण के केदारखंड में इस धाम की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ केदारनाथ की यात्रा करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। उसे आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त होती है।

केदारनाथ केवल धार्मिक महत्व का केंद्र नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और प्रकृति के अद्भुत संबंध का भी प्रतीक है। यहां पहुंचकर व्यक्ति को एहसास होता है कि प्रकृति और परमात्मा एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। हिमालय की ऊंची चोटियां, बहती नदियां, शीतल हवाएं और मंदिर की घंटियों की ध्वनि मिलकर ऐसा वातावरण बनाती हैं जो मन को भीतर तक स्पर्श कर जाता है।

हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस धाम में पहुंचते हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, कोई कृतज्ञता व्यक्त करने आता है और कोई केवल आध्यात्मिक शांति की खोज में यहां पहुंचता है। लेकिन लगभग हर श्रद्धालु यहां से लौटते समय एक नया अनुभव अपने साथ लेकर जाता है।

केदारनाथ हमें केवल एक पौराणिक कथा नहीं सुनाता, बल्कि जीवन का गहरा संदेश भी देता है। पांडवों की तरह मनुष्य भी गलतियां करता है, संघर्षों से गुजरता है और कभी-कभी अपराधबोध से घिर जाता है। लेकिन सच्चा पश्चाताप, आत्मचिंतन और ईश्वर के प्रति समर्पण उसे नई दिशा दे सकते हैं। यही संदेश बाबा केदार की भूमि से सदियों से मिलता आ रहा है।

आज भी जब कोई भक्त हिमालय की ऊंचाइयों के बीच स्थित इस दिव्य धाम में पहुंचकर त्रिकोणीय शिवलिंग के दर्शन करता है, तो उसे केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं दिखाई देता। उसे दिखाई देती है हजारों वर्षों की आस्था, तपस्या, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा। यही कारण है कि केदारनाथ को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि शिव की जीवंत उपस्थिति का स्थान माना जाता है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सुरंगों के रास्ते दौड़ेगा भारत का भविष्य, पालघर में तेज हुई बुलेट ट्रेन परियोजना की रफ्तार

देश की पहली हाईस्पीड रेल परियोजना ने पार किया एक और अहम पड़ाव, महाराष्ट्र में तीसरी पहाड़ी सुरंग की खुदाई पूरी; अगले वर्ष परिचालन की दिशा में बढ़ा बड़ा कदम

मुंबई। भारत के परिवहन इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर तेजी से आकार ले रहा है। आधुनिक भारत के सपनों को नई गति देने वाली इस परियोजना ने महाराष्ट्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पालघर जिले के दहानू तहसील स्थित अंबेसरी गांव में बुलेट ट्रेन के लिए बनाई जा रही तीसरी पहाड़ी सुरंग की खुदाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इस उपलब्धि को देश की पहली हाईस्पीड रेल सेवा को जमीन पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) के अनुसार, अंबेसरी में तैयार की गई यह सुरंग 417 मीटर लंबी और 14.4 मीटर चौड़ी है। इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि बुलेट ट्रेन दोनों दिशाओं में अत्यधिक गति और उच्च सुरक्षा मानकों के साथ संचालित हो सके। सुरंग निर्माण की सफलता ने परियोजना की प्रगति को नई गति प्रदान की है और यह संकेत दिया है कि लंबे समय से प्रतीक्षित बुलेट ट्रेन अब धीरे-धीरे वास्तविकता में बदल रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में सुरंग निर्माण किसी भी रेल परियोजना का सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण हिस्सा होता है। भूगर्भीय परिस्थितियों, सुरक्षा जोखिमों और तकनीकी जटिलताओं के कारण ऐसे निर्माण कार्यों में अत्यधिक सावधानी और आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता होती है। पालघर में पूरी की गई यह सुरंग इसी चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा थी, जिसे आधुनिक इंजीनियरिंग कौशल और उन्नत तकनीकों की सहायता से सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

एनएचएसआरसीएल ने बताया कि सुरंग की खुदाई दोनों सिरों से नियंत्रित ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग तकनीक के माध्यम से की गई। निर्माण के दौरान सुरक्षा, गुणवत्ता और पर्यावरणीय प्रभावों पर विशेष ध्यान दिया गया। परियोजना से जुड़े इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों ने लगातार निगरानी करते हुए यह सुनिश्चित किया कि आसपास के क्षेत्रों, गांवों और प्राकृतिक संरचनाओं पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

निर्माण के दौरान अत्याधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। सुरंग की मजबूती, जमीन की स्थिति और संरचनात्मक स्थिरता की निगरानी के लिए रियल-टाइम तकनीकों को अपनाया गया। सरफेस सेटलमेंट पॉइंट्स (SSP), थ्री-डायमेंशनल टारगेट, स्ट्रेन गेज और सीस्मोग्राफ जैसे उन्नत उपकरणों के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी गई। इन उपकरणों की सहायता से जमीन में होने वाले सूक्ष्म बदलावों, कंपन की तीव्रता और संरचनात्मक प्रभावों का लगातार विश्लेषण किया जाता रहा।

बुलेट ट्रेन परियोजना के अधिकारियों का कहना है कि सुरंग निर्माण के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रही। सुरंग के भीतर पर्याप्त वेंटिलेशन की व्यवस्था की गई ताकि ताजी हवा का प्रवाह बना रहे। इसके साथ ही आग से सुरक्षा के लिए आधुनिक अग्निशमन प्रणालियां स्थापित की गईं। निर्माण स्थल पर प्रवेश और निकास को नियंत्रित रखा गया तथा तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा चौबीसों घंटे निगरानी की जाती रही। सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन के कारण निर्माण कार्य बिना किसी बड़े व्यवधान के पूरा किया जा सका।

पिछले पांच महीनों के दौरान महाराष्ट्र में तीन महत्वपूर्ण पहाड़ी सुरंगों की खुदाई पूरी होना परियोजना की प्रगति का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। वापी और बोईसर बुलेट ट्रेन स्टेशनों के बीच स्थित तीनों पहाड़ी सुरंगों का निर्माण अब सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इन्हें MT-08, MT-07 और MT-06 नाम दिया गया है। इन सुरंगों की पूर्णता से कॉरिडोर के महत्वपूर्ण हिस्से में निर्माण कार्य को और अधिक गति मिलेगी।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत कुल आठ पहाड़ी सुरंगों का निर्माण प्रस्तावित है। इनमें सात सुरंगें महाराष्ट्र के पालघर जिले में और एक सुरंग गुजरात के वलसाड जिले में बनाई जा रही है। यह पूरा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण माना जाता है, इसलिए यहां सुरंग निर्माण को परियोजना का सबसे कठिन चरण माना गया था। अब लगातार मिल रही सफलताओं से यह स्पष्ट हो गया है कि इंजीनियरिंग और निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना केवल एक परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता, आधुनिक अवसंरचना और आर्थिक विकास का प्रतीक मानी जा रही है। जापान के सहयोग से विकसित की जा रही यह परियोजना भारत में हाईस्पीड रेल नेटवर्क की नींव रखेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके सफल होने के बाद देश के अन्य हिस्सों में भी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अगले वर्ष 15 अगस्त तक बुलेट ट्रेन के प्रारंभिक संचालन की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। प्रारंभिक चरण में गुजरात के हिस्से में सेवा शुरू किए जाने की संभावना जताई गई है। इससे यात्रियों को पहली बार भारत में विश्वस्तरीय हाईस्पीड रेल यात्रा का अनुभव मिलेगा।

मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है। इस मार्ग पर बुलेट ट्रेन 320 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। वर्तमान में मुंबई और अहमदाबाद के बीच ट्रेन यात्रा में लगभग छह से सात घंटे का समय लगता है, जबकि बुलेट ट्रेन के संचालन के बाद यही दूरी लगभग दो घंटे में पूरी की जा सकेगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि व्यापार, उद्योग, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। इस परियोजना के तहत कुल 12 स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें आठ गुजरात और चार महाराष्ट्र में स्थित होंगे। प्रमुख स्टेशनों में मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स से लेकर साबरमती तक के कई महत्वपूर्ण शहर शामिल हैं। स्टेशन परिसरों को आधुनिक सुविधाओं, डिजिटल तकनीक और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बुलेट ट्रेन परियोजना का प्रभाव केवल परिवहन तक सीमित नहीं रहेगा। इसके आसपास नए औद्योगिक क्षेत्र, लॉजिस्टिक हब, व्यावसायिक केंद्र और रोजगार के अवसर विकसित होंगे। निर्माण चरण में हजारों लोगों को रोजगार मिला है, जबकि संचालन शुरू होने के बाद भी बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

'मेक इन इंडिया' पहल के तहत विकसित की जा रही इस परियोजना में भारतीय इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इससे देश में हाईस्पीड रेल तकनीक के क्षेत्र में नई विशेषज्ञता विकसित हो रही है। भविष्य में यह अनुभव अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए भी उपयोगी साबित होगा।

पालघर में तीसरी सुरंग की सफल खुदाई केवल एक निर्माण उपलब्धि नहीं, बल्कि उस बड़े परिवर्तन का संकेत है जो आने वाले वर्षों में भारत की परिवहन व्यवस्था को नई पहचान देने वाला है। सुरंगों, पुलों, आधुनिक स्टेशनों और हाईस्पीड ट्रैक के माध्यम से तैयार हो रहा यह कॉरिडोर भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल करेगा, जहां विश्वस्तरीय बुलेट ट्रेन नेटवर्क संचालित होता है। देश की पहली बुलेट ट्रेन के सपने को साकार करने की दिशा में यह उपलब्धि एक और मजबूत कदम मानी जा रही है।

तिरुमाला मंदिर में बाल चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि से टीटीडी को करोड़ों का राजस्व प्राप्त हुआ

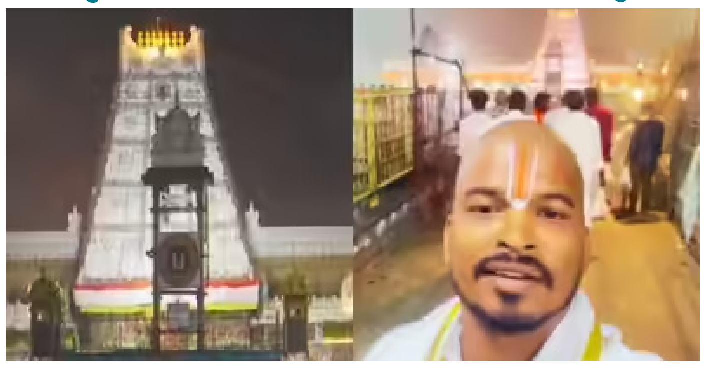

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। आंध्र प्रदेश के विश्व के सबसे धनी मंदिर तिरुमाला में, 1 से 27 मई के बीच 12,43,063 श्रद्धालुओं ने अपने सिर मुंडवाकर भगवान को अर्पित किए। यह आंकड़ा पिछले दो वर्षों के मई माह में सिर मुंडवाने वालों की संख्या से कहीं अधिक है। मई 2025 में 10,18,370 श्रद्धालुओं ने और मई 2024 में 10,65,729 श्रद्धालुओं ने सिर मुंडवाया था।

भगवान वेंकटेश्वर, जिन्हें बोलचाल की भाषा में तिरुपति बालाजी भी कहा जाता है, को बाल अर्पित करने की परंपरा ग्रीष्म ऋतु में काफी बढ़ गई है। पिछले महीने के पहले 27 दिनों में सिर मुंडवाने वाले भक्तों की संख्या ने विश्व के सबसे बड़े "कल्याण कट्टा" या मुंडन केंद्र का रिकॉर्ड बना दिया है।

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के अधिकारियों ने बालों के दान में हुई वृद्धि का कारण मौजूदा भीषण गर्मी को बताया है। मानव बाल को काला सोना कहा जाता है और दुनिया भर के बाजारों में इसकी काफी मांग है।

टीटीडी मानव बाल बेचकर प्रतिवर्ष 130 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करता है। यह आस्था और सेवा का अनूठा संगम है। आय का एक बड़ा हिस्सा मंदिर में जमा होता है।

बंगाल में अमूल का 600 करोड़ का मेगा दांव, हावड़ा में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा दही संयंत्र,रोजाना 10 लाख किलोग्राम दही, लस्सी और छाछ का होगा उत्पादन, डेयरी उद्योग में आएगी नई क्रांति

पश्चिम बर्दवान। देश के डेयरी क्षेत्र में एक नया इतिहास लिखने की तैयारी शुरू हो गई है। भारत के सबसे बड़े दुग्ध सहकारी ब्रांड अमूल ने पश्चिम बंगाल में 600 करोड़ रुपये के विशाल निवेश की घोषणा कर डेयरी उद्योग को नई दिशा देने का संकेत दिया है। कंपनी हावड़ा जिले के संकरेल फूड पार्क में दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र स्थापित करने जा रही है। यह परियोजना केवल एक औद्योगिक निवेश नहीं बल्कि पूर्वी भारत के डेयरी क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है।

अमूल द्वारा प्रस्तावित यह अत्याधुनिक डेयरी परिसर उत्पादन क्षमता, तकनीकी सुविधाओं और प्रसंस्करण क्षमता के मामले में दुनिया के सबसे बड़े दही संयंत्रों में शामिल होगा। इस परियोजना के शुरू होने के बाद प्रतिदिन 10 लाख किलोग्राम दही, लस्सी और छाछ का उत्पादन किया जाएगा। इतनी बड़ी उत्पादन क्षमता भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक डेयरी उद्योग में भी एक नया मानक स्थापित करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में पूर्वी भारत में डेयरी उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में दही की पारंपरिक संस्कृति और स्थानीय स्वाद को देखते हुए यह निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बंगाल में 'टोक दोई' और 'मिष्टी दोई' केवल खाद्य उत्पाद नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। ऐसे में अमूल की यह परियोजना स्थानीय मांग और राष्ट्रीय बाजार दोनों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस परियोजना की घोषणा पहली बार बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 के दौरान की गई थी। अब इसके क्रियान्वयन की दिशा में तेजी से काम आगे बढ़ाया जा रहा है। परियोजना को दो चरणों में विकसित किया जाएगा ताकि उत्पादन क्षमता और बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तार किया जा सके। राज्य सरकार और डेयरी क्षेत्र के विशेषज्ञ इसे पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रहे हैं।

अमूल के प्रबंध निदेशक जयेन मेहता ने बताया कि प्रस्तावित इकाई केवल दही निर्माण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे एक समेकित डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस आधुनिक परिसर में प्रतिदिन 15 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता होगी। इससे यह संयंत्र देश के सबसे बड़े डेयरी प्रसंस्करण केंद्रों में शामिल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि दही, लस्सी और छाछ के अलावा यहां आइसक्रीम, पनीर, घी, फ्लेवर्ड मिल्क तथा यूएचटी (अल्ट्रा हाई टेम्परेचर) दूध का भी उत्पादन किया जाएगा। इससे उत्पादों की विविधता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को एक ही परिसर से कई प्रकार के डेयरी उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पश्चिम बंगाल को डेयरी प्रसंस्करण के एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित होने का अवसर मिलेगा।

अमूल पहले से ही पश्चिम बंगाल में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुका है। वर्तमान में कंपनी राज्य में प्रतिदिन 10 लाख लीटर से अधिक दूध की बिक्री कर रही है। इसके साथ ही कंपनी ने राज्य के 14 जिलों में व्यापक दूध संग्रहण नेटवर्क स्थापित किया है। इस नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों परिवार डेयरी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। कंपनी के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में उसके दूध संग्रहण अभियान से 1.2 लाख से अधिक महिला दुग्ध उत्पादक सीधे जुड़ी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं दूध उत्पादन और आपूर्ति के माध्यम से अपनी आय बढ़ा रही हैं। नए संयंत्र के शुरू होने के बाद दूध की मांग में और वृद्धि होगी, जिससे हजारों नए किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।

ग्रामीण विकास विशेषज्ञों का मानना है कि डेयरी क्षेत्र कृषि के बाद ग्रामीण आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभरा है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है, वहां डेयरी उद्योग अतिरिक्त आय का मजबूत माध्यम बन सकता है। अमूल की नई परियोजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह बढ़ाने और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार यह निवेश केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं बल्कि पूर्वी भारत के डेयरी बाजार की विशाल संभावनाओं पर आधारित रणनीतिक निर्णय है। वर्ष 2024 में पश्चिम Bengal का डेयरी बाजार लगभग 89 हजार करोड़ रुपये का आंका गया था। उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2033 तक यह बाजार 12 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर से आगे बढ़ सकता है। ऐसे में अमूल का यह निवेश भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर किया गया दीर्घकालिक कदम माना जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि भारत में दही और अन्य किण्वित डेयरी उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है।

छगनभाई सोलंकी: वाल्मीकि समुदाय के उत्थान, शिक्षा और जन जागरूकता में अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। छगनभाई सोलंकी ने वर्षों तक अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कांग्रेस के नेता के रूप में कार्य किया। वे सन् 1960 से समाज के जरूरतमंद बच्चों को पाठ्यपुस्तकें और नोटबुक उपलब्ध कराते आ रहे थे। वडोदरा शहर के वाल्मीकि समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे अंबालाल मोतीलाल सोलंकी मोरखाला, दलपतसिंह सोलंकी गोत्री, मगनभाई देसाई वडोदरा, वडोदरा जिले के अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता सोमभाई कालिदास सोलंकी, रश्मिकांत शंकरलाल वैष्णव, मनीलाल सोलंकी और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वडोदरा शहर और जिले के वाल्मीकि समुदाय के उत्थान और समाज के विकास के लिए सराहनीय कार्य किए, लेकिन छगनभाई सोलंकी की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। सन् 1950 से 1980 के बीच वे वडोदरा शहर में कई बड़े सम्मेलन और सभाएं आयोजित करते थे और सामाजिक जागरूकता के लिए प्रयास करते थे। उनके दुखद निधन पर गुजरात प्रदेश वाल्मीकि समाज और गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष भाई लाल बी. वैष्णव ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। ईश्वर उनकी आत्मा को शाश्वत शांति प्रदान करें। गुजरात प्रदेश वाल्मीकि समाज के महासचिव कांतिभाई सोलंकी आदि ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि वे उनके परिवार पर आई विपत्ति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

गुजरात तट पर बढ़ती मादक पदार्थों की तस्करी: सुरक्षा बलों और माफिया नेटवर्क के लिए एक बड़ी चुनौती

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। गुजरात के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसकी विशाल तटरेखा है। इसलिए, इस लंबी तटरेखा पर चलने वाले बड़ी संख्या में पंजीकृत छोटे जहाजों और नौकाओं की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना अनिवार्य है। यह तटरेखा वाणिज्यिक और सुरक्षा दोनों ही दृष्टियों से संवेदनशील क्षेत्र है। अतः, सीमा पार तस्करी के माध्यम से पूरे देश में मादक पदार्थों की लत का जाल फैलाने वाले संगठित गिरोहों पर शिकंजा कसना अत्यंत आवश्यक है।

देश में अवैध मादक पदार्थों का बढ़ता प्रचलन एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। इसका प्रसार तेजी से हो रहा है। यह खतरा बड़े शहरों से लेकर दूरदराज के गांवों तक फैल चुका है। भूमि और समुद्री मार्गों से अन्य देशों से मादक पदार्थों की बड़े पैमाने पर तस्करी जारी है। हाल ही में, तटरक्षक बल और गुजरात आतंकवाद-विरोधी दस्ते (एटीएस) ने एक संयुक्त अभियान में कच्छ के मुंद्रा तट के पास एक जहाज से लगभग 1150 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए। सवाल यह है कि गुजरात अधिकाधिक मादक पदार्थों का पारगमन केंद्र क्यों बनता जा रहा है? पिछले कुछ वर्षों से राज्य में सुरक्षा बल इस तरह की अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। इन तमाम प्रयासों के बावजूद अगर समुद्री मार्गों से होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम नहीं लग पा रही है, तो इसके मूल कारण क्या हो सकते हैं? आखिर सुरक्षा एजेंसियां समुद्री मार्गों से इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी करने और उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में वितरित करने वाले मुख्य अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ क्यों हैं? क्योंकि पिछले पांच वर्षों से गुजरात के तटीय इलाकों में लगातार हो रही ड्रग्स की बरामदगी से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ ड्रग्स की तस्करी लगातार जारी है। जब तक इन ड्रग माफिया नेटवर्क को जड़ से खत्म नहीं किया जाता, तब तक ये मौत के सौदागर ड्रग्स के जहर से हमारे देश को तबाह करते रहेंगे। देश का विकास जारी रहेगा, लेकिन देश को विनाश की ओर ले जा रहे इन दुष्ट तत्वों की पहचान करना और उन्हें तुरंत खत्म करना बेहद जरूरी है।

फोस्टा चुनाव का बिगुल बजा, 41 डायरेक्टर पदों के लिए होगी जंग

सूरत। दक्षिण गुजरात के सबसे प्रभावशाली व्यापारिक संगठनों में शामिल फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन (फोस्टा) के आगामी कार्यकारिणी चुनावों का शंखनाद हो चुका है। वर्ष 2026-29 के कार्यकाल के लिए नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू करते हुए चुनाव समिति ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही सूरत के विशाल कपड़ा बाजार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और विभिन्न मार्केटों में संभावित उम्मीदवारों तथा समर्थकों के बीच रणनीतिक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। फोस्टा चुनाव अधिकारी अशोक जैन, बृजमोहन अग्रवाल और सचिन अग्रवाल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आगामी कार्यकाल के लिए कुल 41 डायरेक्टरों का निर्वाचन किया जाएगा। यह चुनाव केवल प्रतिनिधि सदस्यों के लिए मान्य होगा और निर्धारित पात्रता रखने वाले सदस्य ही मतदान करने तथा चुनाव लड़ने के अधिकारी होंगे।

सूरत का कपड़ा उद्योग देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल व्यापारिक केंद्रों में गिना जाता है और फोस्टा इस उद्योग की प्रमुख प्रतिनिधि संस्था है। व्यापारियों की समस्याओं, नीतिगत मुद्दों, प्रशासनिक समन्वय और उद्योग हितों की पैरवी में फोस्टा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यही कारण है कि इसके चुनावों को कपड़ा उद्योग की राजनीति और नेतृत्व का महत्वपूर्ण मंच माना जाता है।

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार इच्छुक उम्मीदवार 4 जून से 6 जून 2026 तक मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट स्थित फोस्टा कार्यालय से नामांकन पत्र प्राप्त कर सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित होगी। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित की गई है। इसके बाद 8 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और पात्र उम्मीदवारों की प्रारंभिक सूची जारी होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 9 जून रखी गई है। इसी दिन शाम को अंतिम उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी, जिसके बाद चुनावी मुकाबले की तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी।

यदि उम्मीदवारों की संख्या निर्धारित पदों से अधिक रहती है तो 20 जून 2026, शनिवार को मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट परिसर में होगा। मतदान समाप्त होते ही उसी दिन शाम 6 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी और परिणामों की घोषणा भी कर दी जाएगी।

इस बार फोस्टा चुनाव में कुल 1663 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव समिति द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लेटिनम श्रेणी में 302, डायमंड श्रेणी में 222, गोल्ड श्रेणी में 937 तथा मार्केट श्रेणी में 202 मतदाता पंजीकृत हैं। इन मतदाताओं के वोट से आगामी तीन वर्षों के लिए संगठन का नेतृत्व तय होगा। चुनाव समिति ने पात्रता से संबंधित नियमों को भी स्पष्ट कर दिया है। केवल वही प्रतिनिधि सदस्य चुनाव लड़ने और मतदान करने के पात्र होंगे, जिन्हें 30 अप्रैल 2026 तक मान्यता प्राप्त मार्केट एसोसिएशनों द्वारा विधिवत नामित किया गया हो। साथ ही उम्मीदवार का रंगीन कपड़े के व्यापार से जुड़ा होना अनिवार्य रखा गया है।

विशेष नियमों के तहत प्रत्येक मार्केट से प्लेटिनम, डायमंड और गोल्ड श्रेणी में केवल एक-एक उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतर सकेगा। उम्मीदवारों को संबंधित मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष का लिखित समर्थन पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। चुनाव समिति का मानना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और प्रतिनिधित्व आधारित बनेगी।

नामांकन शुल्क 11,000 रुपये तथा लागू जीएसटी निर्धारित किया गया है। हालांकि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर नाम वापस लेता है तो उसे 5,000 रुपये तथा संबंधित जीएसटी राशि वापस कर दी जाएगी। नामांकन के समय उम्मीदवार की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी और उसे दो पासपोर्ट आकार के फोटो तथा वैध पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति भी जमा करनी होगी।

चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और गरिमामय बनाए रखने के लिए चुनाव समिति ने विस्तृत आचार संहिता भी जारी की है। इसके तहत चुनाव प्रचार में जाति, धर्म, क्षेत्रवाद या व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी उम्मीदवार द्वारा अभद्र भाषा, धनबल, बाहुबल या अनुचित प्रभाव का प्रयोग करने पर कार्रवाई की जा सकती है। समिति ने स्पष्ट किया है कि समाचार पत्रों, टीवी चैनलों अथवा अन्य प्रचार माध्यमों में भुगतान आधारित व्यक्तिगत विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित करना चुनाव नियमों के विरुद्ध माना जाएगा। चुनाव प्रचार केवल निर्धारित मर्यादाओं और संगठनात्मक नियमों के अनुरूप ही किया जा सकेगा। मतदान प्रक्रिया को भी पूरी तरह व्यवस्थित बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

गुजरात पुलिस की नूतन पहल

पुलिस भवन में शुरू हुआ 'जनसंपर्क कार्यालय' नागरिकों के लिए बना विश्वास का नया पता

- गुजरात पुलिस की 'सुरक्षा, सेवा और विश्वास' की भावना को उजागर करने वाला सशक्त माध्यम बना जनसंपर्क कार्यालय : राज्य के पुलिस महानिदेशक डॉ. के. एल. एन. राव
- नागरिकों की समस्याओं का सिंगल-विंडो जैसी पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से समय पर समाधान
- राज्य के पुलिस महानिदेशक ने केंद्र का दौरा कर कामकाज की समीक्षा की

गांधीनगर : राज्य के नागरिकों और पुलिस तंत्र के बीच विश्वास तथा पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस भवन में 'जनसंपर्क कार्यालय' शुरू किया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक डॉ. के. एल. एन. राव के मार्गदर्शन में संचालित इस कार्यालय के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों, आवेदनों और समस्याओं का उचित एवं न्यायसंगत समाधान समय पर किया जा रहा है। मंगलवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक ने इस केंद्र का दौरा कर इसके कामकाज की समीक्षा की।

पुलिस विभाग द्वारा शुरू की गई यह व्यवस्था आज नागरिकों के लिए न्याय प्राप्त करने का सुव्यवस्थित और सशक्त माध्यम बन चुका है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक आवेदक की बात को सम्मानपूर्वक सुनना, जिला एवं शहर स्तर की पुलिस कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित कर समयबद्ध और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। इस व्यवस्था से आवेदनों पर कार्रवाई में होने वाली देरी समाप्त हुई है और पुलिस के प्रति जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।

राज्य के पुलिस महानिदेशक डॉ. के. एल. एन. राव ने कहा कि जनसंपर्क कार्यालय केवल नागरिकों के आवेदन स्वीकार करने का केंद्र नहीं है, बल्कि यह गुजरात पुलिस की 'सुरक्षा, सेवा और विश्वास' की भावना को साकार करने का एक सशक्त माध्यम है। कार्यालय की सीढ़ियां चढ़कर आने वाला प्रत्येक सामान्य और गरीब व्यक्ति यहां से न्याय की आशा और संतोष के साथ लौटे, यह हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि जनसंपर्क कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदनों को प्राथमिकता देकर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर भी निर्देश दिए गए हैं।

पहले नागरिकों को शिकायत या प्रस्तुति दर्ज कराने के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब इस सिंगल-विंडो जैसी पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से समय पर शिकायतों का निवारण संभव हो पाया है। आइए, जनसंपर्क केंद्र की संपूर्ण कार्यप्रणाली को समझते हैं :

आवेदन स्वीकार करना और प्रारंभिक पंजीकरण

केंद्र पर आने वाले प्रत्येक नागरिक का विवरण रिसेप्शन डेस्क पर दर्ज किया जाता है। उन्हें सुनवाई के लिए अनुकूल और तनावमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाता है।

अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष सुनवाई

उपस्थित वरिष्ठ एवं जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आवेदक प्रस्तुतियों को ध्यानपूर्वक सुनकर मामले का विवरण दर्ज किया जाता है।

पंजीकरण और त्वरित प्रक्रिया

केंद्र के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों और प्रस्तुतियों का विधिवत पंजीकरण कर आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित जिला अथवा शहर पुलिस इकाइयों एवं संबद्ध शाखाओं को भेजा जाता है।

रिपोर्ट तथा समीक्षा

फील्ड यूनिट के पास से निर्धारित समय में जरुरी रिपोर्ट मंगाकर उसका सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है तथा आगे की कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

दो स्तरीय फीडबैक प्रणाली

सेवा सुधार के लिए कार्यालय एवं जिला स्तर; इन दो प्रकारों से विस्तृत फीडबैक फॉर्म भरवाए जाते हैं। टेलीफोन द्वारा संपर्क कर केस की प्रगति की जानकारी भी दी जाती है।

गत 2 फरवरी से शुरू किए गए इस जनसंपर्क कार्यालय में प्राप्त शिकायतों में से अधिकांश का त्वरित तथा सटीक निवारण किया गया है। भावनगर के श्री जिगरभाई भट्ट ने गांधीनगर स्थित जनसंपर्क कार्यालय का संपर्क किया। कार्यालय के त्वरित फॉलोअप तथा पीआई पलक व पीएसआई एम. जे. पटेल के सहयोग से आवेदक की सम्बद्ध आईपीएस श्रीमती अमिता वनाणी से मुलाकात करवाकर उनके केस के आरोपी को त्वरित गिरफ्तार किया गया और उनकी समस्या का निवारण किया गया। साणंद के आवेदक नरेशभाई दुलेरा ने इस सेवा को आम आदमी के लिए न्याय की आशा किरण तथा जनहित के लिए शुरू की गई उत्तम पहल बताया। जनसंपर्क कार्यालय केवल आवेदन स्वीकार करने का केन्द्र नहीं है, बल्कि पुलिस एवं जनता के बीच विश्वास का सुदृढ़ सेतु है। यह नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण पुलिस प्रशासन को अधिक लोकभोग्य, लोकोपयोगी और जिम्मेदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

‘लोकल से ग्लोबल’ की सशक्त उड़ान : गुजरात सरकार की हस्तकला सेतु योजना बनी परंपरागत कला-कारीगरी के लिए मजबूत प्रोत्साहन का सेतु

▸▸ हस्तकला सेतु योजना अंतर्गत 102.08 करोड़ रुपए की बिक्री, 50,000 से अधिक रोजगार का सृजन
▸▸ योजनांतर्गत 21,690 से अधिक कारीगरों का पंजीकरण, जिनमें 82 प्रतिशत महिलाएँ
▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन को भली-भाँति आगे बढ़ा रहे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर, 02 जून : गुजरात की समृद्ध हस्तकला परंपरा की सदियों से देश-विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान है। बदलते आर्थिक परिप्रेक्ष्य तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के समय में इन कारीगरों को सशक्त बनाना समय की बड़ी आवश्यकता बनी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी ‘विकास भी, विरासत भी’, ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘वोकल फॉर लोकल’ जैसे मंत्रों द्वारा परंपरागत कला विरासत को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने का विजन दिया है और गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल इस विजन को भली-भाँति आगे बढ़ा रहे हैं।

प्रधानमंत्री के इसी विजन तथा परंपरागत कला विरासत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने वर्ष 2020 में ‘हस्तकला सेतु योजना’ (एचएसवाई) शुरू की थी, जो आज कला-कारीगरों के लिए मजबूत आर्थिक प्रोत्साहन का सेतु सिद्ध हुई है।

हस्तकला सेतु योजना पर गुजरात सरकार द्वारा 58 करोड़ रुपए का खर्च

गुजरात में हस्तकला सेतु योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है, जिसके कारण राज्य के हजारों कारीगरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। इस योजना का क्रियान्वयन कुटीर एवं ग्रामोद्योग आयुक्त के अधीनस्थ इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन-कॉटेज (इंडेक्स्ट-सी) द्वारा किया जा रहा है, जबकि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) ने इस योजना में नॉलेज पार्टनर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शुरुआत में यह योजना 2019-20 से तीन वर्ष के लिए प्रस्तावित थी, परंतु कोविड-19 महामारी के चलते इसे 2025-26 तक विस्तृत किया गया। इस योजना पर राज्य सरकार द्वारा लगभग 58 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका विशाल दायरा है। यह योजना गुजरात के सभी 34 जिलों में लागू की गई है। योजनांतर्गत अब तक 21,690 से अधिक कारीगरों का पंजीकरण किया गया है, जिनमें 82 प्रतिशत महिलाएँ हैं। सामाजिक समावेशिता की दृष्टि से भी यह योजना महत्वपूर्ण है, कारण कि लाभार्थियों में 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 20 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा 34 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के कारीगर शामिल हैं।

15 हजार से अधिक कारीगरों को उद्यमिता प्रशिक्षण, 70 से अधिक मास्टर ट्रेनर्स तथा 150 से अधिक मेंटर्स का नेटवर्क

हस्तकला सेतु योजनांतर्गत कारीगरों को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण भी दिया गया है। 15,586 कारीगरों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि 9,292 कारीगरों को उनके क्षेत्र से जुड़ा विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण मिला है। इसके अतिरिक्त; 70 से अधिक मास्टर ट्रेनर्स तथा 150 से अधिक मेंटर्स का नेटवर्क तैयार किया गया है, जो कारीगरों को निरंतर मार्गदर्शन दे रहा है।

9,300 कारीगरों को बीटूबी ऑर्डर द्वारा सीधे बाजार से जोड़ा गया, 102.08 करोड़ रुपए की कुल बिक्री दर्ज हुई

बाजार के साथ कनेक्टिविटी इस योजना का सबसे मजबूत पहलू है। लगभग 9,300 कारीगरों को बीटूबी ऑर्डर द्वारा सीधे बाजार से जोड़ा गया है। इसके अलावा; 7 बीटूबी मीट तथा 4 फैशन शो द्वारा कारीगरों एवं डिजाइनरों के बीच सुदृढ़ संवाद स्थापित हुआ है। डिजिटल युग के अनुरूप 2,000 से अधिक कारीगरों को डिजिटल मार्केटिंग का प्रशिक्षण देकर उन्हें अमेजन, फ्लिपकार्ट समर्थ, मीशो तथा इट्सी जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है।

इस योजना का आर्थिक प्रभाव भी बहुत प्रभावशाली रहा है। योजनांतर्गत अब तक 102.08 करोड़ रुपए की कुल बिक्री दर्ज हुई है और 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। साथ ही; मौजूदा 5,900 से अधिक कारीगरों को अतिरिक्त सहायता एवं मार्गदर्शन मिला है।

योजनांतर्गत आय अर्जित करने वाले कला-कारीगरों की संख्या 9 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत तक पहुँची

यदि कारीगरों की आय की बात करें, तो हस्तकला सेवा सेतु योजना से पहले केवल 9 प्रतशत कारीगर ही 15,000 रुपए से अधिक मासिक आय अर्जित कर पाते थे, जबकि आज यह आँकड़ा 50 प्रतिशत तक बढ़ गया है। हस्तकला को आय के मुख्य स्रोत के रूप में अपनाने वाले कारीगरों की संख्या भी 20 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत हो गई है। इसके अलावा; 73 प्रतिशत कारीगर अब प्रदर्शनियों तथा मेलों द्वारा सीधे बाजार तक पहुँच बना रहे हैं।

यद्यपि योजना के सफल क्रियान्वयन के दौरान कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। इनमें दस्तावेजों का अभाव, वित्तीय समन्वय में विलंब, आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाने में संकोच तथा प्रभावी मार्केटिंग तंत्र का अभाव प्रमुख हैं, परंतु गुजरात सरकार ने इन चुनौतियों को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, डिजाइन नवीनता, बाजार विविधता तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्राथमिकता दी। हस्तकला सेतु योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि कारीगरों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली एक क्रांतिकारी पहल बनी है। इस योजना ने केवल रोजगार सृजन ही नहीं किया, बल्कि गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है। ‘लोकल टू ग्लोबल’ की ओर यह कदम भारत को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

कोठगांगड़ गांव के निकट रेलवे द्वारा रिकॉर्ड समय में निर्मित जल निकासी संरचना से ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत

जन समस्याओं के निवारण करने की अपनी सतत प्रतिबद्धता के तहत पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल ने मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के दिशा निर्देशों के अनुरूप साबरमती–बोटाद रेलखंड पर कोठगांगड़ गांव के निकट किलोमीटर 76/6-7 पर 2 मीटर × 2 मीटर आकार के आरसीसी बॉक्स ब्रिज (जल मार्ग) का निर्माण एवं स्थापना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया है। यह महत्वपूर्ण कार्य मात्र दो माह के रिकॉर्ड समय में पूर्ण किया गया।

दिनांक 01 जून 2026 को 200 टन क्षमता वाले क्रेन की सहायता से बॉक्स ब्रिज का सुरक्षित एवं सटीक रूप से सफलतापूर्वक इंसर्शन (Insertion) किया गया। इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा तथा मानसून के दौरान वर्षा जल के सुचारु प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

विगत कई वर्षों से कोठगांगड़ गांव एवं पांजरापोल क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान जलभराव की समस्या उत्पन्न होती रही है, जिससे ग्रामीणों एवं पशुपालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। स्थानीय प्रतिनिधियों की मांग के अनुसार नव निर्मित 2 मीटर × 2 मीटर आकार का यह जल निकास वर्षा जल की निर्बाध निकासी सुनिश्चित करेगा तथा जलभराव की समस्या को काफी हद तक कम करने में सहायक सिद्ध होगा।

भावनगर मंडल द्वारा समयबद्ध योजना, तकनीकी दक्षता एवं समर्पित प्रयासों से पूर्ण की गई यह परियोजना रेलवे की जनहित एवं क्षेत्रीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह कार्य न केवल रेलवे अवसंरचना को मजबूत करेगा, बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के जीवन को भी अधिक सुगम एवं सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

03 जून को वडोदरा मंडल के वासद–रनोली स्टेशनों के बीच ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेने प्रभावित रहेगी

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल पर वासद-रनोली स्टेशनों के बीच ब्रिज नं. 624 (अप लाइन) पर री-गर्डरिंग कार्य हेतु 03 जून (बुधवार) को 11.15 बजे से 16.45 बजे तक 05.30 घंटे का मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। जिसके कारण वडोदरा मंडल से चलने/गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी। जो इस प्रकार हैः

पूर्णतः निरस्त ट्रेन

03 जून 2026 की ट्रेन संख्या 19036 मणिनगर–वड़ोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस पूर्णतः निरस्त रहेगी।

03 जून 2026 की ट्रेन संख्या 19035 वड़ोदरा-मणिनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस पूर्णतः निरस्त रहेगी।

03 जून 2026 की ट्रेन संख्या 12930 वड़ोदरा- वलसाड इंटरसिटी एक्सप्रेस पूर्णतः निरस्त रहेगी।

आंशिक निरस्त ट्रेन

03 जून 2026 की ट्रेन संख्या 22960 जामनगर-वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस अहमदाबाद स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा अहमदाबाद-वडोदरा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

रिशेड्यूल होने वाली ट्रेन

1. 03 जून 2026 की ट्रेन संख्या 12010 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस 40 मिनिट रिशेड्यूल रहेगी।

रेगुलेट होने वाली ट्रेने

1. 03 जून 2026 की ट्रेन संख्या 16533 भगत की कोठी–केएसआर बैंगलुरु एक्सप्रेस 55 मिनिट रेगुलेट रहेगी।
2. 03 जून 2026 की ट्रेन संख्या 12477 जामनगर–श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस 50 मिनिट रेगुलेट रहेगी।
3. 03 जून 2026 की ट्रेन संख्या 20626 भगत की कोठी–एमजीआर चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस 55 मिनिट रेगुलेट रहेगी।

यात्रियों से निवेदन है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी! जबलपुर-सोमनाथ एक्सप्रेस में महिला ने बच्चे को दिया जन्म, मां एवं नवजात दोनों सुरक्षित

भारतीय रेल की यात्री सेवा एवं मानवीय संवेदनशीलता का एक प्रेरणादायक उदाहरण उस समय देखने को मिला, जब गाड़ी संख्या 11466 जबलपुर–सोमनाथ एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक गर्भवती महिला ने चलती ट्रेन में ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। रेलवे कर्मचारियों की तत्परता, सहयात्रियों के सहयोग तथा विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट समन्वय से प्रसव सुरक्षित रूप से संपन्न हुआ। वर्तमान में मां एवं नवजात दोनों स्वस्थ हैं तथा विरमगाम के अस्पताल में उनका उपचार एवं चिकित्सकीय देखभाल जारी है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 02 जून, 2026 को अहमदाबाद से वेरावल की यात्रा कर रही एक गर्भवती महिला यात्री, जो कोच संख्या S-2 में अपने पति के साथ सफर कर रही थीं, को अहमदाबाद स्टेशन से ट्रेन प्रस्थान करने के कुछ समय बाद अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। स्थिति की जानकारी महिला के पति एवं अन्य यात्रियों द्वारा ऑन ड्यूटी टिकट निरीक्षक (TTE) श्री रामजीवन कुमार को दी गई।

सूचना प्राप्त होते ही श्री रामजीवन कुमार ने बिना विलंब किए भावनगर मंडल के वाणिज्य नियंत्रण कार्यालय को स्थिति से अवगत कराया तथा तत्परता से रेलवे बेडशीट उपलब्ध कराया। इस बीच चांदलोडिया स्टेशन पार होने के बाद प्रसव पीड़ा बढ़ने पर कोच में उपस्थित महिला सहयात्रियों ने अत्यंत संवेदनशीलता एवं साहस का परिचय देते हुए गर्भवती महिला की सहायता की। उनके सहयोग से चलती ट्रेन में ही सुरक्षित प्रसव कराया गया और महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन ने आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं। विरमगाम स्टेशन पर पूर्व समन्वय के तहत चिकित्सा सहायता एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। महिला के पति की सहमति प्राप्त होने के उपरांत मां एवं नवजात को सुरक्षित रूप से ट्रेन से उतारकर एम्बुलेंस के माध्यम से विरमगाम के सरकारी अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों द्वारा जांच के पश्चात बताया गया कि मां एवं नवजात दोनों की स्थिति सामान्य एवं स्वस्थ है।

पूरे घटनाक्रम के दौरान ऑन ड्यूटी टीटीई श्री रामजीवन कुमार ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए महिला एवं उसके परिजनों के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई तथा चाय-पानी की व्यवस्था भी करवाई। उनकी तत्परता एवं कर्तव्यनिष्ठा की यात्रियों द्वारा सराहना की गई।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने इस सराहनीय कार्य के लिए संबंधित कर्मचारियों, विशेष रूप से ऑन ड्यूटी टीटीई श्री रामजीवन कुमार तथा सहयोग करने वाली महिला यात्रियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि रेलवे केवल यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का माध्यम नहीं, बल्कि आवश्यकता के समय उनके साथ खड़े रहने वाली एक संवेदनशील संस्था भी है। उन्होंने कर्मचारियों को भविष्य में भी इसी प्रकार यात्रियों की सहायता एवं सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने हेतु प्रोत्साहित किया। यात्री परिवार ने रेलवे प्रशासन, ऑन ड्यूटी स्टाफ एवं सहयोग करने वाले सहयात्रियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनकी त्वरित सहायता और मानवीय व्यवहार की सराहना की।

प्रतापनगर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कायाकल्प

वडोदरा का प्रतापनगर स्टेशन अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह वर्ष 1880 में नैरो गेज रेलवे के आगमन का प्रमुख केंद्र रहा है। वर्ष 1922 में यहां प्रतापनगर में एक महत्वपूर्ण रेलवे वर्कशॉप की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इस स्टेशन को एक रणनीतिक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे वडोदरा स्टेशन पर यातायात का दबाव कम किया जा सके। यहां लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन तथा आधुनिक यात्री सुविधाओं की योजना है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और यात्रियों की सुविधा में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण बोर्डिंग स्टेशन भी है।

वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के अनुसार प्रतापनगर रेलवे स्टेशन का यह व्यापक पुनर्विकास न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करेगा, बल्कि वडोदरा शहर की रेलवे अवसंरचना को भी नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यात्री सुविधाओं का विस्तार :

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 71.58 करोड़ रुपये की लागत से प्रतापनगर रेलवे स्टेशन का व्यापक पुनर्विकास का कार्य किया गया है जिससे इस स्टेशन को एक नया भव्य स्वरूप मिला है। पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत पुराने 1, 2 एवं 3 नंबर प्लेटफॉर्मों पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। साथ ही एक नए प्लेटफॉर्म नंबर 4 का विकास किया गया है, जिसमें उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्मों का विस्तार एवं पुनर्सतहीकरण किया गया है। प्लेटफार्मों पर आधुनिक प्लेटफॉर्म शेल्टर तैयार किये गए है जिससे यात्रियों को बैठने की सुगम व्यवस्था उपलब्ध हो। नए स्टेशन भवन में नए विभिन्न कार्यालयों की स्थापना की गयी है। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण किया गया है। साथ ही आधुनिक साइनेज व्यवस्था तथा दिव्यांगजन-अनुकूल बुकिंग काउंटर सुविधाओं का विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्टेशन पर दो नई लिफ्टों की स्थापना भी की गई है।

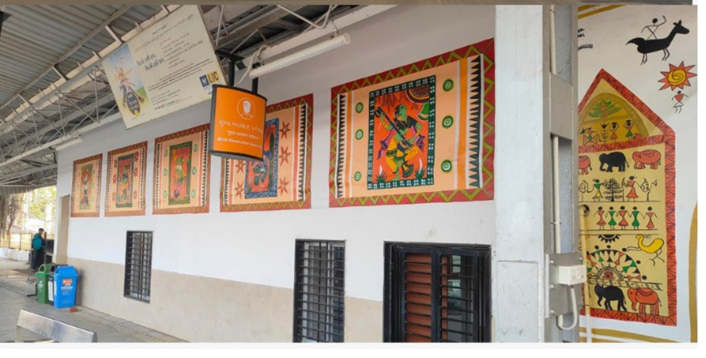

आकर्षक द्वितीय प्रवेश द्वार :

प्रतापनगर स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार की तरफ नए स्टेशन भवन का निर्माण तथा वाणिज्यिक क्षेत्र के विकास का कार्य भी किया गया है, जिससे स्टेशन भवन का स्वरूप बेहद आकर्षक हुआ है। सेकंड एंट्री क्षेत्र में सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन, पर्याप्त पार्किंग सुविधा, स्पष्ट प्रवेश एवं निकास मार्ग तथा आधुनिक शहरी अवसंरचना विकसित की गई है।

कॉन्कोर्स क्षेत्र का आधुनिकीकरण :

यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से स्टेशन के कॉन्कोर्स क्षेत्र का भी आधुनिकीकरण किया गया है। आधुनिक फ्लोरिंग के साथ आकर्षक वॉल क्लैडिंग की गयी है, जिसमें रेलवे के इतिहास की झलक को उकेरा गया है। स्टेशन पर उन्नत प्रकाश व्यवस्था के साथ स्टेशन परिसर में कलात्मक भित्ति चित्र (म्यूरल्स) स्थापित किए गए हैं, जो स्टेशन को एक नया और आकर्षक स्वरूप प्रदान करते हैं।

दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाएं :

दिव्यांगजन यात्रियों के लिए प्लेटफार्म को सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक सुलभ सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।दिव्यांगजन-अनुकूल बुकिंग काउंटर सुविधाओं का विकास किया गया है। फुट ओवर ब्रिज को लिफ्टों से भी जोड़ा गया है जिससे यात्रियों को प्लेटफार्मों पर जाने में सुगमता हासिल हो, जिससे यह स्टेशन पूर्णतः दिव्यांगजन-अनुकूल बन सके।

आवागमन को सुगम बनाता 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज :

स्टेशन के दोनों ओर के शहर तथा प्लेटफार्मों को जोड़ने के लिए 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु दोनों सिरों पर रैंप की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही फुट ओवर ब्रिज को लिफ्टों से भी जोड़ा गया है जिससे यात्रियों को प्लेटफार्मों पर जाने में सुगमता हासिल हो, जिससे यह स्टेशन पूर्णतः दिव्यांगजन-अनुकूल बन सके।

यह परियोजना भारतीय रेल के “यात्री सुविधा, सुगम यात्रा और आधुनिक स्टेशन” के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री योगेशभाई पटेल के निधन पर गहरा शोक और दुःख व्यक्त किया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री योगेशभाई पटेल के निधन पर गहरा शोक और दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत योगेशभाई को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रसेवा और जनसेवा के कार्यों में निरंतर कर्तव्यनिष्ठ रहकर आम जनता के हृदय में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने परम कृपालु परमात्मा से प्रार्थना की कि दिवंगत योगेशभाई की आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोकसंतप्त परिवार और उनके समर्थकों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दें।

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल का शानदार प्रदर्शनः मई 2026 में 688 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व, यात्री और मालभाड़ा आय में भारी उछाल

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने मई 2026 के दौरान विभिन्न वाणिज्यिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्व अर्जन, माल परिवहन, यात्री सुविधाओं के विस्तार तथा गैर-किराया आय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। मंडल ने इस महीने लगभग 688 करोड़ का सकल राजस्व (Gross Revenue) अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष मई 2025 की तुलना में 7.01% अधिक है।

राजस्व के मुख्य आंकड़ेः

▸▸ यात्री राजस्व (Passenger Revenue)ः 22.68% की भारी बढ़ोतरी के साथ 144.95 करोड़ दर्ज किया गया, जो पिछले साल मई में 118.15 करोड़ था।

▸▸ अन्य कोचिंग राजस्व (Other Coaching Revenue)ः पिछले वर्ष के 16.47 करोड़ से 52.40% बढ़कर 25.10 करोड़ तक पहुंच गया।

▸▸ मालभाड़ा राजस्व (Goods Revenue)ः मई 2026 में 517.34 करोड़ रहा, जिसमें पिछले साल (507.72 करोड़) की तुलना में लगभग 2% की वृद्धि देखी गई।

▸▸ यात्रियों की संख्याः प्रारंभिक यात्रियों की संख्या (No. of Orig. Passengers) 12.67% बढ़कर 34.15 लाख हो गई।

मालभाड़े (Freight) में ऐतिहासिक रिकॉर्डः

अहमदाबाद मंडल के कई प्रमुख टर्मिनलों और साइडिंग्स ने अब तक का अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ मासिक मालभाड़ा राजस्व दर्ज किया हैः

▸▸ देशलपर (DSLP) फ्रेट टर्मिनलः 13.40 करोड़ का अब तक का सर्वश्रेष्ठ राजस्व हासिल किया।

▸▸ इफ्को (IFFCO) साइडिंग खोडियारः 9.98 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया।

▸▸ सानोसरा (SNSR) फ्रेट टर्मिनलः 10.75 करोड़ का अपना सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया ।

▸▸ बेंटोनाइट लोडिंग (Bentonite Loading)ः बेंटोनाइट की लोडिंग से मंडल को 24.29 करोड़ का ऐतिहासिक मासिक राजस्व प्राप्त हुआ।

▸▸ बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट (BDU) के विशेष प्रयासः

मंडल की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट (BDU) ने नए ग्राहकों, गंतव्यों और नई सामग्रियों को जोड़कर राजस्व बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैः

▸▸ नई सामग्रीः आईटीसी लिमिटेड द्वारा कांडला पोर्ट से पोल्लाची जंक्शन तक ‘सोयाबीन एक्सट्रैक्शन और फ्लेक्स’ की पहली मिनी रेक लोड की गई, जिससे 42.06 लाख का अतिरिक्त राजस्व मिला।

▸▸ नए ग्राहकः मेसर्स मैग्नस माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड ने सानोसरा से भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड की निजी साइडिंग तक बेंटोनाइट की रेक भेजकर 1.07 करोड़ का राजस्व उत्पन्न किया ।

▸▸ औद्योगिक नमक, बेंटोनाइट और जैविक खाद जैसी सामग्रियों को देश के विभिन्न डिवीजनों (जैसे वडोदरा, भावनगर, सिकंदराबाद, कोटा, पुणे, जम्मू और खुर्दा रोड) के नए गंतव्यों तक सफलतापूर्व भेजा गया ।

नॉन-फेयर रेवेन्यू (NFR) और पार्सल में नवाचारः

▸▸ गेम जोन अनुबंधः महेसाणा (MSH) स्टेशन पर 454 वर्ग मीटर क्षेत्र में पांच वर्षों के लिए ‘गेम जोन’ के विकास और संचालन का ई-ऑक्शन कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक आवंटित किया गया, जिससे 44.25 लाख का राजस्व मिलेगा ।

▸▸ पार्सल ई-ऑक्शनः मई महीने में आयोजित ई-ऑक्शन के माध्यम से 11 पार्सल संपत्तियों को तीन साल के लिए लीज पर दिया गया, जिससे 20.08 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है ।

▸▸ मसालों की पार्सल रेकः महेसाणा से अज़ारा और ऊंझा से मिर्ज़ा के लिए मसालों की पहली पार्सल रेक चलाई गईं, जिससे क्रमशः 24.79 लाख और 27.15 लाख का राजस्व मिला।

यात्री सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

▸▸ ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने हेतु 33 विशेष ट्रेन यात्राओं का संचालन किया गया तथा 43 अतिरिक्त कोच लगाए गए।

▸▸ इन प्रयासों से लगभग 0.55 लाख यात्रियों को सुविधा प्रदान की गई तथा 6.79 करोड़ का अतिरिक्त यात्री राजस्व अर्जित हुआ।

भुज-दिल्ली एक्सप्रेस का शुभारंभः 22 मई 2026 को माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जालौर-पाली मारवाड़ के रास्ते पहली बार ‘भुज से भुज-दिल्ली एक्सप्रेस’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे कच्छ और देश की राजधानी के बीच कनेक्टिविटी मजबूत हुई है । टिकट चेकिंग और स्वच्छता अभियानः बिना टिकट और अनियमित यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न स्टेशनों पर विशेष (Fortress) जांच अभियान चलाए गए, जिससे मई महीने में लगभग 3.00 करोड़ की टिकट चेकिंग आय होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, स्टेशनों पर गंदगी फैलाने और थूकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एंटी-लिटरिन्ग मामलों के तहत 1.38 लाख का जुर्माना वसूल किया गया।